

» कृषि

» विश्लेषण

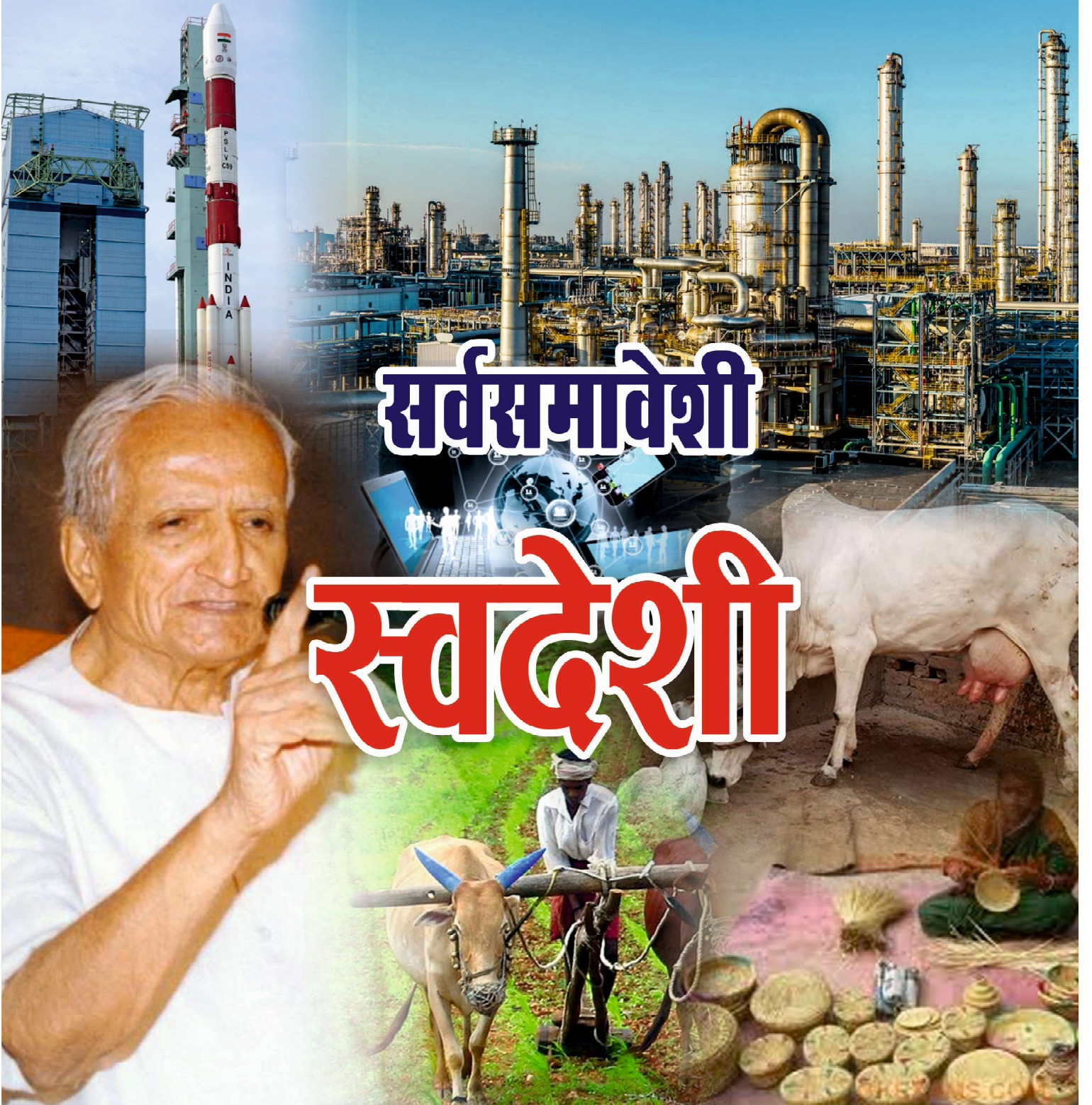
» जल प्रबंधन

कुल पृष्ठ: 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/-रु.

अश्विन-कार्तिक 2082, अक्टूबर 2025

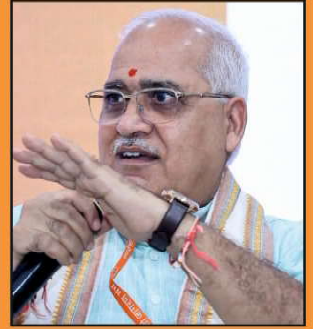


स्वदेशी गतिविधियां

केंद्रीय समिति बैठक

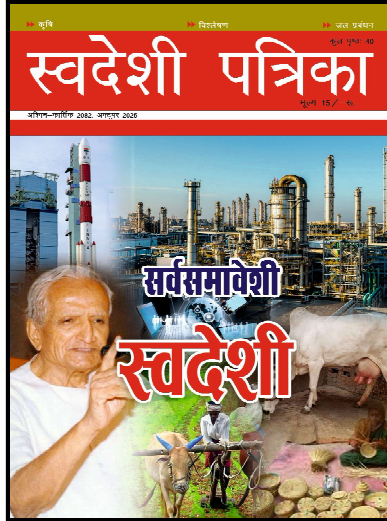
20-21 सितंबर 2025 (हैदराबाद)

सचित्र श्रलक



स्वदेशी सप्ताह, भोपाल





वर्ष-33, अंक-10
अश्विन-कार्तिक 2082 अक्टूबर 2025

संपादक
अजेय भारती

सह-संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर-8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011-26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ.
अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्प्यूटेंट बाइन्डर्स
(प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली-32
से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**



तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा - पृष्ठ-06

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वदेशी

डॉ. अश्वनी महाजन



- 1 मुख्य पृष्ठ
- 2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ
- 08 स्वदेशी
विकास का स्वदेशी मॉडल
..... दत्तोपंत ठेंगड़ी
- 10 स्वदेशी
शिक्षा क्षेत्र में स्वदेशी
..... सरोज कुमार मित्र
- 11 स्वदेशी
गांधी जयंती पर विशेष: गांधी जी और स्वदेशी
..... अनिल तिवारी
- 13 स्वदेशी
विकास हेतु स्वदेशी को जरूरी मानते थे श्री गुरुजी
..... स्वदेशी संवाद
- 15 स्वदेशी
स्वदेशी और स्वावलंबन से ही हासिल होगा विकसित भारत का लक्ष्य
..... अनिल जोशी
- 17 स्वदेशी
ग्राम स्वास्थ्य सेवाएं समग्र बनें
..... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र
- 19 स्वदेशी
कृषि एवं स्वदेशी दृष्टि
..... शिवनंदन लाल
- 21 स्वदेशी
स्वदेशी कृषि एवं गोरक्षण
..... वरुण कुमार पाण्डेय
- 23 स्वदेशी
खुशहाली मुफ्तखोरी में नहीं, स्वदेशी, स्वावलंबन से प्राप्त आत्मनिर्भरता में
..... स्वदेशी संवाद
- 25 स्वदेशी
स्वदेशी से ही निकलेगा समाधान
..... अनूप पांडेय
- 27 चर्चा
'विस्तृत हो गया है स्वदेशी का दायरा': श्री कश्मीरी लाल
- 30 विचार
एकात्म मानव दर्शन का सर्वोदय
..... अनिल जवलेकर
- 32 स्वदेशी गतिविधियां
केंद्रीय कार्यसमिति बैठक - हैदराबाद (तेलंगाना)
..... स्वदेशी संवाद

स्वदेशी और लघु उद्योगों को कैसे बढ़ावा देता है नवरात्रि का पर्व

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक मनाया गया। हर साल शारदीय नवरात्रि मनाया जाने वाला यह त्यौहार बंगाल में दुर्गा पूजा, गुजरात एवं महाराष्ट्र में डांडिया-गरबा नृत्य, और उत्तर भारत में जागरण जैसी विविध सांस्कृतिक प्रथाओं का संगम है। यह व्यापक उत्सव खुदरा व्यापार, रियल एस्टेट, सोना बिक्री, आतिथ्य और स्थानीय हस्तशिल्प जैसे कई क्षेत्रों में भारी आर्थिक उछाल लाता है।

भारत में इसके आर्थिक प्रभाव का आकलन करें तो नवरात्रि के पहले दिनों में सोने की कीमतों में 2 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई, जो समृद्धि के लिए सोना खरीदने की परंपरा से प्रेरित है, और इससे ज्वेलर्स तथा ट्रेडर्स को लाभ हुआ। रियल एस्टेट में भी उत्सव के दौरान 15-20 प्रतिशत की मांग बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि डेवलपर्स ने छूट और विशेष वित्तपोषण की पेशकश की। केवल उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों ने प्रमुख मंदिरों का दौरा किया, जिससे यात्रा, भोजन, आवास और स्थानीय व्यापार में वृद्धि हुई। धार्मिक वस्तुएं, त्योहारी पोशाक, सजावट और हस्तशिल्प बनाने वाले स्थानीय कारीगरों और एमएसएमई को बढ़ती मांग का फायदा मिला।

यह पर्व स्वदेशी और लघु उद्योगों का समर्थन विशेष रूप से करता है। नवरात्रि का सांस्कृतिक महत्व उपभोक्ताओं को देशी उत्पादों की ओर प्रोत्साहित करता है, जिससे पारंपरिक कारीगर और छोटे निर्माता लाभान्वित होते हैं। इस मौसमी मांग से ग्रामीण और सूक्ष्म व्यवसायों में नकदी प्रवाह और रोजगार सुदृढ़ होते हैं, साथ ही प्राचीन शिल्प कौशल बनी रहती है।

2025 में वैश्विक जीडीपी संदर्भ में बात करें तो भारत 4.19 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ विश्व का 4वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, जो अमेरिका (30.5 ट्रिलियन), चीन (19.23 ट्रिलियन) और जर्मनी (4.74 ट्रिलियन) के बाद है। नवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान घरेलू उपभोग की मजबूती इस वृद्धि में योगदान देती है, जो भारत की आर्थिक संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, शारदीय नवरात्रि भारत के लिए एक शक्तिशाली आर्थिक उत्प्रेरक है, जो पारंपरिक उद्योगों और आधुनिक क्षेत्रों दोनों को बढ़ावा देता है, साथ ही देश की वैश्विक आर्थिक उपस्थिति को भी सुदृढ़ करता है।

विजित कुमार (स्वदेशी कार्यकर्ता), दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

“धर्मक्षेत्र” शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर-8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली-110022

दूरभाष : 011-26184595 • ई-मेल:

swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क 'स्वदेशी पत्रिका' दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपये

आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपये

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

यदि शुल्क जमा करने के उपरान्त भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

कहा-अनकहा



स्वदेशी का मतलब सिर्फ विदेशी सामान का बहिष्कार करना नहीं है, बल्कि देश के भीतर बने उत्पादों को प्राथमिकता देना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार अपनी शर्तों पर, दबाव में नहीं करना है।

डॉ. मोहन भागवत, सरसंघचालक, संघ



“हमें हर घर और हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। रोजमर्रा की विदेशी वस्तुओं से मुक्त होकर हमें मेड इन इंडिया को अपनाना होगा ताकि देश की समृद्धि स्वदेशी से मजबूत हो सके।”

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत



स्वदेशी का अर्थ भारतीय श्रम, भारतीय भूमि और हमारे कारीगरों की मेहनत से बने उत्पाद हैं। यही रोजगार सृजन का असली आधार है।

पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री, भारत



राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 100 वर्षों में स्वदेशी विचारधारा के पोषण और प्रचार में एक विशिष्ट भूमिका निभाई है। संघ के लिए स्वदेशी को भारत की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों में निहित एक सभ्यतागत लोकाचार के रूप में देखा गया है।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सह-संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

अमेरिकी शटडाउन: अमेरिकी व्यवस्था की कमज़ोरी उजागर

जबकि दुनिया इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए अनुचित और बहुपक्षीय व्यापार नियमों के विरुद्ध टैरिफ पर चर्चा कर रही है, एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर अभी तक विस्तृत चर्चा नहीं हुई है, वह है— अमेरिकी सरकार का शटडाउन, जो 1 अक्टूबर, 2025 से चल रहा है और 4 नवंबर को इस शटडाउन ने पिछले ट्रंप प्रशासन के दौरान 2018 के पिछले 35 दिनों के शटडाउन को पीछे छोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 1 अक्टूबर से, अमेरिकी सरकार का कामकाज लगभग ठप हो गया है, लगभग 9 लाख संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है, और 20 लाख अन्य को बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। केवल स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य सहायता और परिवहन सुरक्षा प्रशासन जैसी आवश्यक सेवाएँ ही अपवाद हैं। अमेरिकी इतिहास में यह 11वाँ शटडाउन है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी सेवाएँ ठप हो गई हैं। इससे पहले सबसे लंबा शटडाउन 2018–19 में हुआ था, जो पिछले ट्रंप के कार्यकाल में 35 दिनों तक चला था, हालाँकि यह पूर्ण सरकारी शटडाउन नहीं था। ज़रा सोचिए, अगर ऐसा भारत में होता, जहाँ सभी सरकारी प्रतिष्ठान बंद हो जाते और सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता, तो दुनिया भर में, खासकर अमेरिका में, भारतीय संविधान और व्यवस्था की आलोचना करते हुए ढेरों लेख लिखे जाते। फिर भी, अमेरिका में हुई इतनी बड़ी घटना की भी बहुत कम रिपोर्टिंग हो रही है।

अमेरिका में दो प्रमुख पार्टियाँ हैं— रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। गौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं। रिपब्लिकन द्वारा संचालित सदन ने तुरंत एक वित्त पोषण विधेयक पारित किया, लेकिन सीनेट में इसे समर्थन नहीं मिला। डेमोक्रेटिक पार्टी का दावा है कि स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी (खासकर अफोर्डेबल केयर एक्ट से संबंधित) बजट में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, कांग्रेस की शिकायत है कि राष्ट्रपति प्रशासन बजट प्रक्रिया में कांग्रेस की शक्तियों का अतिक्रमण कर रहा है। कांग्रेस को डर है कि बिना शर्त बजट अनुमोदन कांग्रेस की शक्तियों का हनन होगा। शटडाउन ने न केवल सरकारी कामकाज को ठप कर दिया है, बल्कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए खाद्य सहायता, खासकर पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (स्नैप) के बंद होने का भी खतरा पैदा कर दिया है। कुछ विभागों ने सैन्य कर्मियों को वेतन सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र से भी धन जुटाया है। गौरतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 नवंबर, 2026 को बड़े पैमाने पर चुनाव होने वाले हैं। इन मध्यावधि चुनावों में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और अमेरिकी सीनेट की 100 में से 35 सीटों के लिए चुनाव होंगे, जिससे 120वीं संयुक्त राज्य कांग्रेस का गठन होगा। 29 राज्य और क्षेत्रीय गवर्नर चुनाव, साथ ही कई राज्य और स्थानीय चुनाव भी लड़े जाएँगे। अमेरिका में आगामी मध्यावधि चुनाव वास्तव में सरकारी बंद के त्वरित या स्थायी समाधान में बाधा बन रहे हैं। राष्ट्रीय हित पर आम सहमति से ज़्यादा राजनीतिक गुणा-भाग महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।

हमें यह समझना होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लगातार जारी बंद केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि अमेरिकी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की गहरी संरचनात्मक और वैचारिक कमज़ोरियों का लक्षण है। इतना लंबा शटडाउन अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की प्रतिस्पर्धी हितों, खासकर राजकोषीय विवेक और राजनीतिक लोकलुभावनवाद के बीच सामंजस्य बिठाने में असमर्थता को दर्शाता है। बजट को मंजूरी देने या ऋण सीमा बढ़ाने में विफलता (जैसा कि हमने पहले भी देखा है) एक खंडित लोकतंत्र को दर्शाती है जो निहित स्वार्थों के हाथों बंधक बना हुआ है, जहाँ अल्पकालिक राजनीतिक लाभ दीर्घकालिक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर भारी पड़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की ऋण और घाटे के वित्तपोषण पर असंतुलित निर्भरता से हमें कोई राहत नहीं मिली है। इस शटडाउन ने उजागर किया है कि कैसे अमेरिकी आर्थिक मॉडल लगातार उधार लेने का आदी हो गया है, और राजनीतिक नेता राजकोषीय अनुशासनहीनता के परिणामों का सामना करने को तैयार नहीं हैं। अमेरिकी नीति निर्माताओं के दोहरे मापदंड पूरी तरह से उजागर हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के माध्यम से विकासशील देशों को राजकोषीय जिम्मेदारी का उपदेश देता है, लेकिन घरेलू स्तर पर इसका पालन करने में बुरी तरह विफल रहता है।

हम देखते हैं कि वैश्विक आर्थिक असंतुलन एक तरह से अमेरिकी डॉलर के आधिपत्य से जुड़े हैं। हम समझते हैं कि शटडाउन और बार-बार ऋण सीमा संकट अमेरिकी वित्तीय प्रणाली में वैश्विक विश्वास को कमज़ोर कर रहे हैं। यह दुनिया में डॉलर-विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है और भारत में अस्थिर पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर वित्तीय तंत्र बनाने के विश्वास को मजबूत कर रहा है। कोई भी आसानी से समझ सकता है कि शटडाउन एक व्यक्तिवादी और उपभोग-आधारित आर्थिक व्यवस्था का परिणाम है जो लोगों की तुलना में बाज़ारों को प्राथमिकता देती है। आम अमेरिकी नागरिकों — बिना वेतन वाले सरकारी कर्मचारी, सेवाओं में देशी और सामाजिक असुरक्षा स्पष्ट रूप से इस नव उदारवाद की विफलता का संकेतक है। हालाँकि सामान्य रूप से पश्चिमी मीडिया और विशेष रूप से अमेरिका भारतीय संस्थानों को कमज़ोर दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ता, शटडाउन उस कहानी को ध्वस्त कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पश्चिमी आर्थिक प्रणाली की तुलना में भारत में कहीं बेहतर संस्थागत स्थिरता को है। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, भारत को कभी भी इस तरह के शटडाउन का सामना नहीं करना पड़ा है क्योंकि बजट अनुमोदन को राष्ट्रीय जिम्मेदारी माना जाता है, न कि राजनीतिक सौदेबाज़ी। वास्तव में, अमेरिका का बंद होना उभरती अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर भारत के लिए आत्मनिर्भरता, संतुलित व्यापार और सहकारी संघवाद पर आधारित एक नए वैश्विक आर्थिक नेतृत्व को स्थापित करने का एक अवसर है। जब पश्चिम अपने विरोधाभासों के बोझ तले लड़खड़ाता है, तो भारत को अपने मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, न कि उनके उधार लिए गए मॉडलों के आधार पर।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वदेशी

अगस्त 1905 में, जब स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई, स्वदेशी राजनीतिक आंदोलन का एक माध्यम बन गया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान स्वदेशी विचार प्रक्रिया का हिस्सा बन गया। यह स्वदेशी के विचार का एक व्यावहारिक प्रकटीकरण था, लेकिन मूल विचार विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से कहीं आगे तक फैला था। महात्मा गांधी भारत के अहिंसक औद्योगिक विकास में विश्वास करते थे। हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन ने जल्द ही समाजवाद को अपना लिया; और एक ऐसे दौर में पहुँच गया जहाँ 'आत्मनिर्भरता' जैसे शब्द निजी क्षेत्र को बदनाम करने और निजी उद्यमों के राष्ट्रीयकरण के साथ राज्य-आधारित विकास के प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए उभरे। राज्य की केंद्रीयता ने स्थानीय उद्यमों की स्वदेशी भावना और उनकी जीवंतता का स्थान ले लिया।

बाद में, 90 के दशक की शुरुआत में, व्यापक भुगतान संतुलन संकट, जिसने अंततः 1990 के दशक में अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए मजबूर किया, ने 'आत्मनिर्भरता' और स्वदेशी के विकास मॉडल को फिर से एक दूसरे प्रकार से बदनाम कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहले नेहरूवादी राज्य-प्रायोजित, सार्वजनिक क्षेत्र-आधारित आत्मनिर्भरता मॉडल का विरोध किया था; और संघ द्वारा पुनः बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पूँजी और तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता पर आधारित वैश्वीकरण मॉडल का भी उतना ही मुखर विरोध हुआ। यह कोई रहस्य नहीं है कि आर्थिक सुधारों और विदेशी पूँजी, वस्तुओं और सेवाओं के लिए अर्थव्यवस्था के खुलने से स्थानीय उद्यमों पर भारी दबाव पड़ा है। 2020 से शुरू हुई आत्मनिर्भर भारत की नई पहल को स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि इसका उद्देश्य विदेशी पूँजी और तकनीक पर निर्भरता और प्रभुत्व को कम करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में समाज में बदलाव लाने हेतु जिन पाँच बिंदुओं, जिन्हें पंच परिवर्तन कहा गया है उनमें एक महत्वपूर्ण बिंदु, स्व के भाव का जागरण यानि स्वदेशी भी है। इसके अतिरिक्त समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन और नागरिक कर्तव्य के विषयों को सामाजिक परिवर्तन हेतु रखा गया है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 100 वर्षों में स्वदेशी विचारधारा के पोषण और प्रचार में एक विशिष्ट भूमिका निभाई है। स्वदेशी के बारे में इसकी समझ कभी भी केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं रही, बल्कि संघ के लिए स्वदेशी को भारत की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों में निहित एक सभ्यतागत लोकाचार के रूप में देखा गया है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ऐसे समय में हुई जब स्वतंत्रता संग्राम के तहत स्वदेशी आंदोलन पहले ही गति पकड़ चुका था। लेकिन संघ के लिए स्वदेशी का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना ही नहीं था, बल्कि स्वदेशी उद्योगों, ग्रामीण शिल्प, कृषि और सांस्कृतिक गौरव को पुनर्जीवित करना भी था।

डॉ. हेडगेवार जी का मानना था कि राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ अर्थव्यवस्था और विचारों में आत्मनिर्भरता के माध्यम से समाज को मजबूत बनाना भी आवश्यक है। यानि कह सकते हैं कि संघ प्रारंभ से ही विदेशी के बहिष्कार के साथ ही साथ देश के पुनरुत्थान के लिए व्यापक स्वदेशी की समर्थक रहा है।



राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में समाज में बदलाव लाने हेतु जिन पाँच बिंदुओं, जिन्हें पंच परिवर्तन कहा गया है उनमें एक महत्वपूर्ण बिंदु, स्व के भाव का जागरण यानि स्वदेशी भी है।
— डॉ. अश्वनी महाजन

जब औपनिवेशिक शक्तियों के पुनःउभार के कारण उत्पन्न समस्याओं के संदर्भ में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की गई तो मंच के कार्यों में तीन आयाम जोड़े गए। पहला आयाम रहा, जन जागरण, जिसके अंतर्गत स्वदेशी वस्तुओं, स्थानीय उत्पादों और विदेशी खतरों के संदर्भ में जन जागरण के विषयों को रखा गया।

स्वदेशी का दूसरा आयाम रहा, आंदोलन। भारत की आर्थिक स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखने के लिए स्वदेशी जागरण मंच ने कई आंदोलन भी किए। प्रारंभ में गैट के अंतर्गत होने वाले समझौतों के संदर्भ में देश के हितों की रक्षा हेतु डंकल ड्राफ्ट के विरोध में देश व्यापी आंदोलन स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद विदेशी कंपनियों द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने (और इसके कारण छोटे मछुआरों पर आए संकट) के विरोध में मत्स्य यात्रा निकाली गई। उसके उपरांत अलकबीर के यांत्रिक कत्लखाने के विरोध में वर्धा से अलकबीर तक की 107 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली गई। अपने 34 वर्ष के आस्तित्व के दौरान स्वदेशी जागरण मंच ने अनेकों अभियान और आंदोलन आयोजित किए, जिनमें अधिकांश बार उसे सफलता प्राप्त हुई।

स्वदेशी जागरण मंच के कार्यों में तीसरा आयाम रचनात्मक कार्यों का रहा है। भारत के उद्योगों विशेष तौर पर लघु कुटीर उद्योगों और कारीगरों के हुनर को प्रोत्साहन हेतु स्वदेशी मेलों का आयोजन, लघु ऋणों की व्यवस्था सहित अनेकों प्रकार के रचनात्मक कार्यों में स्वदेशी जागरण मंच संलग्न रहा है।

स्वतंत्रता के बाद, संघ का स्पष्ट अभिमत रहा कि आर्थिक स्वदेशी के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। संघ ने सदैव विकास के पश्चिमी मॉडलों पर अत्यधिक निर्भरता

का विरोध किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत को कृषि, लघु-स्तरीय उद्योगों और समुदाय-आधारित अर्थव्यवस्था में अपनी पारंपरिक शक्तियों का विकास करना चाहिए। हरित क्रांति और औद्योगीकरण के दौर में, संघ का अभिमत था कि विदेशी तकनीक और पूंजी पर अत्यधिक निर्भरता भारत की आत्मनिर्भरता को नुकसान पहुंचा सकती है। संघ का यह मत सही साबित हुआ, जब विदेशी पूंजी और तकनीक पर निर्भरता के कारण भारत के विकास का मार्ग अवरुद्ध होने लगा।

1991 में आर्थिक उदारीकरण के साथ, संघ की प्रेरणा से स्वदेशी जागरण मंच और स्वदेशी आंदोलन ने बहुराष्ट्रीय निगमों और वैश्वीकरण के माध्यम से आर्थिक उपनिवेशीकरण के खतरे के बारे में देश व्यापी जन जागरण अभियान को आगे बढ़ाया।

स्वदेशी जागरण मंच के निम्नलिखित लक्ष्य रहे:

- आत्मनिर्भर आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना।
- अंधाधुंध विदेशी निवेश का विरोध।
- खादी आधारित उद्योगों सहित लघु एवं कुटीर उद्योगों, कृषि और को मजबूत करना।
- किसानों, छोटे व्यापारियों और पारंपरिक व्यवसायों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाना।

मंच ने लगातार विश्व व्यापार संगठन के समझौतों, खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और बौद्धिक संपदा व्यवस्थाओं के खिलाफ अभियान चलाया, जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाते थे।

संघ ने स्वदेशी को न केवल एक आर्थिक विचार के रूप में, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विचार के रूप में भी व्यक्त किया। दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद (1965), जो संघ द्वारा समर्थित एक मौलिक

1991 में आर्थिक उदारीकरण के साथ, संघ की प्रेरणा से स्वदेशी जागरण मंच और स्वदेशी आंदोलन ने बहुराष्ट्रीय निगमों और वैश्वीकरण के माध्यम से आर्थिक उपनिवेशीकरण के खतरे के बारे में देश व्यापी जन जागरण अभियान को आगे बढ़ाया।

दर्शन है, स्वदेशी को भारतीय लोकाचार में निहित समग्र मानव विकास से जोड़ता है। उपभोक्तावादी वैश्वीकरण के विपरीत, स्वदेशी को परिवार, समुदाय और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली को संरक्षित करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है।

पिछले लंबे समय से संघ आत्मनिर्भर भारत के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, जो स्वदेशी सिद्धांतों को प्रतिध्वनित करता है। संघ की सोच के केंद्र में स्थानीय उत्पादन और उपभोग श्रृंखलाएँ (खेत से बाज़ार, खादी, ग्रामोद्योग)। संघ का यह स्पष्ट मानना है कि आयातित मॉडलों के बजाय भारतीय ज़रूरतों पर आधारित तकनीकी नवाचार होना चाहिए। जीडीपी ग्रोथ अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, सतत विकास, पारिस्थितिकी और परंपरा के साथ विकास का संतुलन होना चाहिए। यानि जीडीपी ग्रोथ के साथ पर्यावरणीय संतुलन तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ अपनी परम्पराओं का भी संरक्षण हो और आर्थिक विषमताएं भी न्यून हों। हाल के वर्षों में, संघ से जुड़े संगठनों ने चीन से आयात पर अत्यधिक निर्भरता का विरोध किया और बहिष्कार आंदोलनों और स्वदेशी विकल्पों को मजबूत करने का आह्वान किया है। □□

विकास का स्वदेशी मॉडल

9-11 जनवरी, 2004 को कडी (गुजरात) में सम्पन्न स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रऋषि श्रद्धेय श्री दत्तोपन्त जी ठेंगडी द्वारा दिया गया समारोप उद्बोधन स्वदेशी पत्रिका के पाठकों के लिए अक्षरशः प्रस्तुत है -

— दत्तोपन्त ठेंगडी



यह अन्तिम सत्र है। समारोप के भाषण में एक पद्धति ऐसी है कि सम्मेलन में जो-जो हुआ, उसको संक्षेप में दोहराना पड़ता है और इसका कारण है कि सामान्य आदमी की स्मरणशक्ति कमजोर होती है, किन्तु मैं समझता हूँ कि इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं की स्मरणशक्ति कमजोर नहीं है और इसलिए उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

एक बात जिसका जिक्र आवश्यक है, वह यह है कि स्वदेशी जागरण मंच की विरासत, (लेगेसी) क्या है? 1920 की बात है, यानि आज से 83 साल पहले की बात है, नागपुर में 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस' का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन के स्वागत सदस्य परम पूजनीय डॉ० हेडगेवार जी थे। इसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उस समय भारत के वायुमण्डल समिति के सक्रिय सदस्यों ने 1920 का उल्लेख किया था। 1917 में रूसी क्रान्ति हुई थी, कम्युनिस्टों का शासन रूस में आया था, उसके बाद, हिन्दुस्तान के सभी नेता, लाला लाजपतराय से लेकर पण्डित नेहरू तक, यही विश्वास रखते थे कि दुनिया भर के पूँजीवाद (केपिटलिज्म) को नष्ट करने का काम अब 'कम्यूनिज्म' करने वाला है। इस वायुमण्डल में, सब लोग यह तो जानते हैं कि परम पूजनीय डॉ० हेडगेवार जी कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख थे, किन्तु दूसरी बात नहीं जानते

हैं। उन्होंने झापट किया हुआ एक प्रस्ताव (रिजोल्यूशन), 'ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के पास भेजा था, उसमें कहा गया था कि इस नागपुर के अधिवेशन में 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस' को अपना ध्येय घोषित करना चाहिए। वह द्विविध होना चाहिए, एक — भारत को स्वतंत्र करते हुए उसमें गणतन्त्र की स्थापना और दो— विश्व के सभी देशों को पूँजीवाद के चुंगल से मुक्त करना, यह हमारा ध्येय घोषित होना चाहिए। स्पष्ट है कि अन्य नेताओं के समान डॉ. हेडगेवार जी यह मानने को तैयार नहीं थे कि 'केपिटलिज्म' को खत्म करने का काम 'कम्यूनिज्म' करेगा, ऐसा यदि मानते, तो 'झार्पिंग' ऐसा न होता कि विश्व के सभी देशों को पूँजीवाद के चुंगल से, सभी देशों को पूँजीवाद (केपिटलिज्म) से मुक्त करने का जिम्मा भारत को ही उठाना पड़ेगा। यह उनकी दूरदृष्टि 1920 में प्रकट हुई उसका केवल मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ, वहीं हमारी विरासत है।

अब यह सम्मेलन समाप्त होने को है, यह अन्तिम सत्र है और इसमें हमने वापिस जाने के बाद, यहाँ का क्या संदेश लोगों को देना है, यह बताने की आवश्यकता है। आज की स्थिति हम जानते हैं। एक स्पष्टीकरण देना मैं आवश्यक समझता हूँ। चूँकि इतने साल तक केवल विश्व व्यापार संगठन के बारे में ही आन्दोलनात्मक, संघर्षात्मक

काम करने का जिम्मा स्वदेशी जागरण मंच को उठाना पड़ा, इसके कारण एक गलतफहमी कुछ लोगों की है कि हम केवल विश्व व्यापार संगठन के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज हमारा 'फोकस' 'विश्व व्यापार संगठन' पर है, क्योंकि सबसे बड़ा संकट वो है, तो भी हम जानते हैं कि देश की जनता के लिए इसके अलावा भी कुछ संकट है, वो हमारी आँखों से ओझल नहीं है, भारत सरकार की गलत आर्थिक नीतियाँ और भारतीय उद्योगपतियों की, पूँजीपतियों की तृष्णा, 'मोनोपोली केपिटलिस्ट' बनने की इच्छा, यह दो बड़े संकट हमारी आँखों से ओझल नहीं है, किन्तु इस समय यह सबसे बड़ा, 'इमीडियेट', तात्कालिक संकट है, इस नाते डब्ल्यू.टी.ओ. की ओर हम ध्यान दे रहे हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. की आज की स्थिति का विवरण उद्घाटन भाषण में किया है, वह एक 'क्रूशियल पॉइन्ट' पर आ गया है, ऐसे पॉइन्ट पर कि 'डेवलप कन्ट्रीज' ने जान लिया है कि पहले जैसा होता था कि 'डेवलप कन्ट्रीज' ने आपस में तय कर लेना कि उनके लिए लाभदायक क्या है, और फिर बाकी के लोगों को दबाव में लाकर कहना कि ऐसा वोटिंग करो, अब वह नहीं चलेगा, यह उन्होंने समझ लिया। 'केनकून' की कॉन्फ्रेंस में सब लोगों ने इसको समझ लिया और इसके कारण एक अलग रणनीति वो अपना रहे हैं, जिसका मैंने विवरण किया। संक्षेप में 'अशुभस्य काल हरणम्' माने कोई भी फैसला तुरन्त न हो, क्योंकि आज ऐसे 'क्रूशियल पॉइन्ट' पर पहुँच गए हैं कि विकसित देशों के लिए अनुकूल फैसला होगा तो विकासशील गरीब देशों के लिए वह घातक होगा और विकसनशील गरीब देशों के लिए अनुकूल फैसला होगा, तो विकसित गौरे देशों के लिए वह घातक होगा। ऐसे 'क्रूशियल पॉइन्ट' पर पहुँचने के कारण अभी 'अशुभस्य काल हरणम्'

चल रहा है। ऐसे समय क्या नीति अपनाना? 'अशुभस्य काल हरणम्' लम्बे देर तक नहीं चल सकता। आज जिनके ध्यान में नहीं आया कि यह क्या रणनीति है, सो सब समझ जाएंगे कि यह 'अशुभस्य काल हरणम्' है तो आगे क्या होगा? इसके विषय में निश्चित, ना हम जानते हैं न वो जानते हैं। लेकिन अपनी दृष्टि से इस सम्मेलन का संदेश जो कार्यकर्ताओं को देना है, जनता को देना है, वो यही है कि 'होप फोर दी बेस्ट, प्रिपेयर फोर दी वर्स्ट'। अच्छी से अच्छी परिस्थिति आएगी, ऐसी हम आशा करें, हालाँकि हम जानते हैं कि आने वाली नहीं और खराब से खराब परिस्थिति आई तो उसका मुकाबला करने की हम तैयारी रखे और उस दृष्टि से संगठन मजबूत हो, स्वदेशी जागरण मंच का संगठन का ढाँचा मजबूत हो, हमारा सम्पर्क विस्तृत हो, हर गाँव में हम पहुँचे और स्वदेशी का मंत्र लोगों को बताए और साथ ही साथ और एक बात है जिसका उल्लेख मैं बाद में करने वाला हूँ। तो संगठन और सम्पर्क, यह 'इमिडियेट' काम हमारे सामने है और यह संदेश लेकर हम जा रहे हैं। संगठन की दृष्टि से, हर स्तर पर अच्छी वर्किंग टीम तैयार हो, जिसको कहा जाता है, 'मास्टर माइण्ड ग्रुप'। हर स्तर पर, ग्राम स्तर से लेकर मण्डल, जिला, प्रदेश, केन्द्र के स्तर पर, 'मास्टर माइण्ड ग्रुप' तैयार हो। यह संगठन के लिए आवश्यक है और सम्पर्क तो करना ही है, हर गाँव में जो अशिक्षित लोग हैं, अनाड़ी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है?

पूजनीय महात्मा गांधी को एक बार राजनेताओं ने पूछा कि कोई भी राष्ट्रीय नीति तय करते समय ज्यादा ख्याल में रखने लायक कौनसी बात है? महात्मा जी ने कहा कि राष्ट्रीय नीति तय करते समय इसका ख्याल करो कि 'देहात में जो अनाड़ी, गरीब व्यक्ति पड़ा

हुआ है, उसके ऊपर आपकी राष्ट्रीय नीति का क्या असर होगा? यह ध्यान में रखकर फिर नीति तय करो।' यही आज ध्यान में रखने की आवश्यकता है और इस दृष्टि से संगठन और सम्पर्क, यहाँ से जाने के बाद तुरन्त यह दोनों काम शुरू होने चाहिए, क्योंकि तरह-तरह की परिस्थितियाँ निर्माण हो सकती है। किसी ने कहा कि 'प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट' खराब से खराब परिस्थितियाँ आएगी तो क्या होगा, उसके लिए तैयार रहना चाहिए।

विकसित गौरे देश यह तो समझ गए कि विकसनशील गरीब देश अब अपनी बात केवल दबाव में आकर मानने वाले नहीं, लेकिन वह चुपचाप नहीं है। एक तरफ वार्ता चल रही है, लोगों से बात कर रहे हैं, यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि अरे भाई इश्यू क्या हैं, हमको पता ही नहीं था। आपको आश्चर्य होगा कि विश्व व्यापार संगठन के चेयरमैन प्रकट रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि 'इश्यू' क्या हैं, इसकी कल्पना ही नहीं थी। अब जब बातें कर रहे हैं हम लोगों से, तो कल्पना कर रहे हैं कि 'इश्यू' क्या है? इतने दिन आपने क्या किया? चूंकि दबाव नहीं था, इश्यू समझ लेने की आवश्यकता नहीं थी, तो इस तरह से एक तरफ वो बतोट चला रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ 'सेबोटेज' करने का भी प्रयास हो रहा है। गरीब देशों के नेताओं को, अफसरशाही को खरीदने का प्रयास हो रहा है। उनके पास पैसा बहुत है और जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, हम जानते हैं कि हमारे देश में भी दो तरह की सरकारें हैं। एक तो परमानेंट सरकार, माने अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी और दूसरी टेम्परेरी सरकार, जो चुनाव के बाद आते जाते रहते हैं। परमानेंट सरकार के नौकरशाहों को यह भरोसा है कि यह जो आने जाने वाले मिनिस्टर हैं वो कुछ नहीं जानते इनका अध्ययन नहीं है, इसलिए हम

जो कहेंगे उस डोक्युमेन्ट पर सिगनेचर करने के लिए बाध्य होंगे। यह आत्मविश्वास उनके अन्दर है और ऐसे जब ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसरशाही है, उनमें से कितने लोग खरीदे जा सकते हैं और कितने खरीदे नहीं जा सकते। इसका हिसाब लगाना कठिन है। आजकल समाचार पत्रों में इसकी खबरें आती हैं। समाचार पत्र पढ़ने से आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ 'अनपरचेजेबल' कौन है, जिसकी गिनती करना आसान है और 'परचेजेबल' कौन है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। ऐसे 'परचेजेबल' लोगों के आधार पर अपनी नीति हमें तय करनी है। इसलिए जनता को सावधान करने की आवश्यकता है और इस स्थिति में लाने की आवश्यकता है, जो स्वदेशी जागरण मंच की पहली मिटिंग में दिल्ली में कहा गया था कि इस तरह के जो नौकरशाह हैं, उनको हम खोज लेंगे, उनको हम नग्न करेंगे और उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। माने उनके साथ कोई सामाजिक सम्बन्ध न रहे। उनके पास जाना नहीं, उनके यहाँ नौकरी नहीं करना, उनके कपड़े धोना नहीं, बर्तन धोना नहीं कुछ भी काम करने के लिए उनके पास कोई नहीं जाए। ऐसा सामाजिक बहिष्कार ऐसे लोगों पर किया जाए। यह बात पहली मिटिंग में कही गई थी। आज भी उसी को दोहराने की आवश्यकता है। इस तरह से आज की परिस्थिति में संगठन और सम्पर्क यह दो प्रमुख बातें हैं, जरो इस सम्मेलन के संदेश के नाते लेकर जाना चाहिए।

इन सारी बातों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसे पिछले वर्किंग कमिटी की मिटिंग में हमने कही थी। हमने कहा था कि 'स्वदेशी मॉडल ऑफ डवलपमेंट' माने विकास का स्वदेशी मॉडल क्या हो? यह वर्क आउट करना, 'स्पेल आउट' करना इसकी आवश्यकता हो रही है। उसमें कुछ लोगों को ऐसा लगा कि काहे के लिए विकास की बात

कर रहे हैं। यह तो बड़ी लम्बी बात है, दूर की बात है, किन्तु इस चुनाव में आपने देखा होगा कि यह दूर की बात नहीं है, चुनाव में अलग-अलग राजनैतिक दलों ने विकास को चुनाव का मुद्दा बनाया। चुनाव एवं उत्तम प्रशासन के लिए यह प्रमुख मुद्दे बनाए गए। इससे आपको यह तो कल्पना हुई होगी कि विकास का कितना महत्व है। विकास की कल्पना और उसका 'स्वदेशी मॉडल' बनाना बहुत आवश्यक है। विदेशी मॉडल हमारे लिए काम नहीं कर सकता। जो पश्चिमी मॉडल हैं उसमें उनके 'पैरामीटर' अलग हैं, भौतिक हैं, जी.डी.पी., जी.एन.पी. आधारित हैं। लोगों के पास कितना पैसा है, इन्कम है, यह सारी जो है, यह 'पैरामीटर' उनके हैं, जो सारे के सारे भौतिक हैं। इसको हम पूरे 'पैरामीटर्स' नहीं मानते हैं। पूरा पैरेडेम नहीं मानते हैं, 'पैरेडेम' में वास्तव में उद्देश्य यही होना चाहिए कि हर आदमी को जो उसकी आवश्यकताएँ हैं, मौलिक आवश्यकताएँ हैं, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य इन सब बातों को उसको उपलब्ध करा देना। यह पहली बात और दूसरी कि उस मॉडल के अन्तर्गत हर व्यक्ति का विकास, व्यक्तिगत विकास कैसा होगा? 'पर्सनल डवलपमेन्ट'। इन दो बातों को लेकर 'स्वदेशी मॉडल ऑफ डवलपमेन्ट' विकसित करना चाहिए। किन्तु हम जानते हैं और यह 'वर्किंग कमिटी' के सामने भी कहा गया कि हम लोग तो 'डे टु डे एक्टिविटी' में लगे हुए हैं। हम ऐसे थोड़े से लोग इस बौद्धिक काम के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम 'डे टू डे एक्टिविटी' में लगे हुए हैं, इसलिए हर स्तर पर ऐसा मॉडल तैयार करने के लिए जो बुद्धिमानी चाहिए, ऐसे बुद्धिमानी रखने वाले लोगों की खोज करना, जिसको कहा गया है— 'हंट फोर दी टेलेंट'। यह आवश्यक है, वह अभी से करना आवश्यक है। तो इस तरह से तीन बातें संदेश के रूप में लेकर जाना है— एक मजबूत संगठन, दूसरा विस्तृत सम्पर्क और तीसरा, उपयुक्त बुद्धिमान लोगों की खोज। इन तीन बातों को लेकर हम अपने लोगों के यहाँ जाएँ और उन्हें जागरूक करें। □□

(स्वदेशी पत्रिका से साभार)

शिक्षा क्षेत्र में स्वदेशी

— सरोज कुमार मित्र



डेवकन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1876 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा पुणे में की गई थी। कलकत्ता की 'दा डॉन' पत्रिका के संपादक सतीश चंद्र मुखर्जी ने छात्रों के बीच प्रखर राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने के लिए 1902 में डॉन सोसायटी की स्थापना की थी। 1901 में लाला लाजपत राय ने पंजाब में कारीगरी शिक्षा अर्जित करने का आह्वान दिया। तिलक के मित्र माधोराव कर्मकार ने 1898 में वाराणसी में एक मराठी स्कूल की स्थापना की और चाफेकर क्लब की एक शाखा भी खोली गयी।

लेकिन कार्लाइल और रिसले के विरोध के कारण वंदेमातरम् और स्वदेशी आंदोलन से जुड़े छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों से निकाले जाने के परिणामस्वरूप 16 नवम्बर, 1905 को कलकत्ता में प्राथमिक से माध्यमिक और विश्वविद्यालयों तक शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (एन.सी.ई.) की स्थापना की गई। इस काम के लिए सुबोध मल्लिक ने एक लाख रुपए और मयमनसिंह के जमींदार ब्रज किशोर राय ने पाँच लाख रुपए का सहयोग किया। स्वदेशी और शिक्षा का प्रचार तेजी से पूरे देश में फैल गया। बम्बई से महाराष्ट्र नाटक

मंडली और बालक केशव हेडगेवार नागपुर में चंदा इकट्ठा कर इसे कलकत्ता में शिक्षा परिषद को भेज दिया।

1908 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के अध्यक्ष रास बिहारी घोष को राजमहेंद्री में नागरिक सम्मान प्रदान किया गया और बाद में आंध्र विश्वविद्यालय का गठन किया गया।

अरविंद ने बड़ौदा में 750 रुपए प्रति माह वेतन वाली अपनी नौकरी छोड़ दी और 1906 में 75 रुपए वेतन पर कलकत्ता में बंगाल नेशनल कॉलेज में अध्यक्ष का पद स्वीकार किया। 1908 तक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् द्वारा 25 माध्यमिक स्कूल, 300 प्राथमिक स्कूल तेलिगाँव, पुणे, राजमहेंद्री, मछलीपट्टनम, इलाहाबाद और येतमाल को स्वीकृति दी गई थी। 1908 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के अध्यक्ष रास बिहारी घोष को राजमहेंद्री में नागरिक सम्मान प्रदान किया गया और बाद में आंध्र विश्वविद्यालय का गठन किया गया। हेडगेवार ने येतमाल स्थित स्कूल से मैट्रिक पास किया। स्वदेशी और राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने के लिए 1909 में सत्यवादी (ओडिशा) में गोपबन्धु दास ने स्कूल की स्थापना की थी। □□

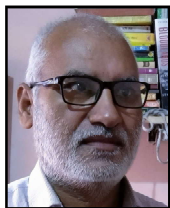
गांधी जी और स्वदेशी

व्यक्ति की श्रेष्ठता की कसौटी क्या है। उसकी प्रशंसा में किया गया तात्कालिक प्रचार अथवा लिखे गए कसीदे या उसके गुणगान में दिए गए जोशीले वक्तव्य? किंतु ऐसा नहीं है। इतिहास साक्षी है कि वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसके चिंतन और कार्यों की छाया भविष्य पर अधिकाधिक लम्बी पड़ती है। गांधी जी ऐसे ही एक श्रेष्ठ पुरुष थे। वह दूरद्रष्टा और भविष्य द्रष्टा थे। उन्होंने वर्षों पूर्व जो कहा था वह आज भी सत्य की कसौटी पर उतना ही खरा है। उनका स्वदेशी आंदोलन केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार अथवा उनकी होली जलाने तक सीमित न होकर समग्र जीवन पद्धति के बाबत था। अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा और प्रताड़ित भारत में वह एक इंकलाब एक जबरदस्त परिवर्तन लाना चाहते थे।

आधुनिक सभ्यता अर्थात् औद्योगिक सभ्यता में मनुष्य मात्र एक उपभोक्ता वस्तु बन कर रह गया है। पिछड़े और विकासशील देशों में आज भी प्रातः मजदूरों की मंडी लगती देखी जा सकती है। विकास के साथ मनुष्य-मनुष्य के मध्य की संवेदनशीलता समाप्त होती दीख रही है और प्यार और स्नेह की जगह 'लाभ' ने ले ली है। अत्यंत तीव्र गति से बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद का जहर शास्वत जीवन मूल्यों का गला घोटता जा रहा है।

परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने सुख के लिए परिवार, समाज और देशहित की बलि देने में भी संकोच का अनुभव नहीं करता। यह अनुभव करके ही गांधी जी ने पश्चिम की सभ्यता को मनुष्य की आत्मा का महाशत्रु कहा था। अतः गांधी जी का स्वदेशी चिंतन वर्तमान में पहले से भी कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। गांधी जी द्वारा लिखी पुस्तक 'हिंद स्वराज्य' में उनकी हार्दिक पीड़ा को समझकर उनके विचारों की गहराई नापी जा सकती है।

गांधी जी के संबंध में किसी के मतभेद हो सकते हैं किंतु यह सत्य है कि उन्होंने जो कुछ कहा और किया वह बिना किसी प्रकार की लाग लपेट के। उन्होंने अपनी तरह से अनेक प्रयोग किए और अपनी कथनी और करनी के भेद को मिटा दिया। 'जियो और जीने दो' के उद्देश्य पूर्ति के लिए उन्होंने सत्य पर आधारित कई सिद्धांत प्रतिपादित किए। विश्व शांति और कल्याण के लिए 'वसुधैव कुटुम्बकम्' उनका आदर्श था। सत्य और अहिंसा उनके गंभीर चिंतन के आधारभूत तत्व थे।



गांधी जी के सपने का
भारत बनाने के लिए हमें
दृढ़ राजनैतिक
इच्छाशक्ति की जरूरत
होगी।

—अनिल तिवारी

'सादा जीवन और उच्च विचार' उनकी श्रेष्ठ जीवन शैली थी। न्यूनतम आवश्यकताएं रखने पर व्यक्ति सुखी रह सकता है, यह उनकी मान्यता और आत्मविश्वास था। स्वावलम्बन, स्वातंत्र्य और स्वराज्य के लिए वह आजीवन कार्यरत रहे। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में प्राप्त राजनैतिक आजादी को अधूरा मानकर उन्होंने 'स्वदेशी चिंतन' पर अपना ध्यान केंद्रित किया और चरखे को भारतीय अर्थनीति का आधार बनाया। जो करोड़ों गरीब भारतीयों के जीवनयापन का संबल बना। व्यक्ति का रहन-सहन, खान-पान, आचार-विचार, भाषा-भेष, चिंतन-मनन जीवन मूल्य तथा आस्थाओं और मान्यताएं, उसकी अपनी स्वदेशी होनी चाहिए। उसे अपने इतिहास और महापुरुषों पर गर्व का गौरव अनुभव करना चाहिए। यह गांधी जी की दृढ़ मान्यता थी। उन्हें भारत में पश्चिम माडल का राजनैतिक और प्रशासनिक ढंग पसंद नहीं था। वह यहां भारतीयों की मानसिक अनुकूलता के अनुरूप पंचायतों और जनपदों पर आधारित लोकतंत्र विकसित किए जाने के पक्षधर थे। उनकी यह मान्यता थी कि अपने संसाधनों से स्थानीय स्तर पर बनी योजना ही ग्रामीण विकास का सफल आधार

हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का यह कहना कि दिल्ली से भेजा गया एक रुपया नीचे आते आते मात्र 15 पैसा रह जाता है और केंद्रीय सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में पंचायती राज के लिए केंद्रीय अधिनियम पारित करना गांधी जी की दूरदृष्टि का ज्वलंत उदाहरण के रूप में देखा गया। गांधी जी चाहते थे कि भारत के कोटि-कोटि सक्षम हाथों में रोजगार के भरपूर अवसर प्राप्त हो और इसके लिए पर्याप्त स्थानीय कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग विकसित किए जाएं। अधिकतम लोगों द्वारा अधिकतम उत्पादन किया जाना उनका निहित उद्देश्य था। इस औद्योगिक प्रक्रिया में वह मशीन का उपयोग न्यूनतम चाहते थे। उनकी यह मान्यता थी कि जितना अधिक मशीनों का प्रयोग होगा, उतने ही अधिक प्रशिक्षित हाथ बेकार हो जाएंगे। वह मशीन विरोधी नहीं थे, किंतु अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति मशीन के पीछे उसके मालिक की नीति के विरोधी थे। वह मशीन के उपयोग की सीमा बांधना चाहते थे। वह चाहते थे कि मशीन से प्राप्त लाभ में मजदूर की बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। उनका कहना था कि चरखे का तकुआ लुहार ही बनावे किंतु टेढ़े तकुए को सीधा करने के लिए मशीन का उपयोग हो सकता है। उनकी समझ का यह सूत्र कितना गहरा है यह हम आज की विद्यमान परिस्थिति में आसानी से समझ सकते हैं। असीमित मशीनीकरण, कम्प्यूटरीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुष्परिणाम आज की बढ़ती बेरोजगारी में हमें स्पष्ट दिख रहे हैं। टाटा, बाटा और बिड़ला के बाद अंबानी और अडानी जैसे भारतीय उद्योगपतियों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत के कितने लुहारों, चर्मकारों, बुनकरों, कुम्हारों, मछुआरों, तेलियों और हलवाई व खोमचे वालों की रोजी-रोटी छीन ली है, क्या

इसका आंकलन हमें है? क्या हमें इसका भी आंकलन नहीं करना चाहिए कि भारत में मिनी सिगरेट बनाने की अनुमति देने के परिणाम स्वरूप आज यहां के कितने बीड़ी श्रमिक और जंगलों में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में लगे बनवासी श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं और विकल्प में जीवित रहने के लिए उन्हें कौन सा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा? हम सब तरफ से आंखे बंद करके गांधी चिंतन को दरकिनार करके किस अंधी गली में दौड़े जा रहे हैं। क्या थोड़ा ठहरकर इस स्थिति पर गंभीर चिंतन करने की जरूरत नहीं है? कहा जाता है कि वर्तमान तकनीकी विकास की चरम सीमा वही होगी जहां एक कारखाने में मात्र दो प्राणी होंगे। एक कुत्ता और दूसरा मनुष्य। कुत्ता कारखाने में किसी को घुसने नहीं देगा तथा मनुष्य कुत्ते के भरण पोषण तथा केवल उसकी देखभाल मात्र करेगा।

आज मशीन मनुष्य की दुश्मन बन गई है। एक ओर वह मनुष्य को बेरोजगार करती है तो दूसरी ओर निकम्मा बना कर रूग्ण कर देती है। जिन मशीनों का उद्देश्य लाभ न होकर मानव कल्याण है, गांधी जी ऐसी मशीनों के विरोधी नहीं थे। वह चाहते थे कि अपनी जरूरत की चीजें हम अपने परंपरागत ढंग से स्वयं ही उत्पन्न और निर्माण करें। उन्होंने पर निर्भरता को त्याग कर स्वावलम्बन, सादगी तथा मितव्ययता पर अधिक जोर दिया।

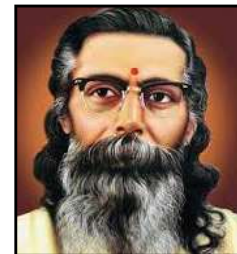
गांधी जी ने अपनी पुस्तक 'हिंद स्वराज्य' में स्वदेशी, स्वावलंबन पर बहुत प्रकाश डाला है। मजदूरों की दशा में सुधार, स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता पर बल दिया है। भारत में पश्चिमी मॉडल के आर्थिक विकास का विरोध करते हुए स्वदेशी से समृद्ध स्वराज की वकालत की है।

हिंद स्वराज पुस्तक के पृष्ठ 55 पर गांधी जी लिखते हैं कि 'जो सभ्यता हिंदुस्तान ने दिखाई है उसके पास

दुनियां में कोई नहीं पहुंच सकता। जो बीज हमारे पुरखों ने बोए हैं उनकी बराबरी कर सके। ऐसी कोई चीज देखने में नहीं आई। रोम शेष हो गया, मिट्टी में मिल गया ग्रीस का सिर्फ नाम ही रह गया, मिस्र की बादशाही चली गई, जापान पश्चिम के शिकंजे में फंस गया। और चीन का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन गिरा टूटा जैसा भी हो हिन्दुस्तान आज भी अपनी बुनियाद में मजबूत है।' वे आगे लिखते हैं कि सभ्यता वह आचरण है जिसमें आदमी अपना फर्ज अदा करता है। फर्ज अदा करने का अर्थ है नीति का पालन करना, नीति के पालन का मतलब है अपने मन और इंद्रियों को बस में रखना। ऐसा करते हुए हम अपने को अर्थात् अपनी असलियत को पहचानते हैं, यही सभ्यता है।

गांधी जी के सपने का भारत बनाने के लिए हमें दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति की जरूरत होगी। मैकाले के षडयंत्र में फंसे भारत को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए यत्नपूर्वक उससे उबारना होगा। उपभोक्तावाद और विदेशी 'बहुराष्ट्रीय कंपनियों' के मोहपाश को कठोरतापूर्वक हमें तोड़ना होगा। यह तभी संभव हो सकता है जबकि हम त्याग और तितिक्षा को आधार बनाकर राजनैतिक स्वार्थों से ऊपर उठ कर, निहित स्वार्थों और प्रलोभनों को छोड़ कर गांधी जी के स्वदेशी चिंतन के अनुरूप अपने 'स्व' पर गौरव अनुभव करते हुए अपने आज के जीवन के हर पहलू पर पुनर्विचार करें। इस आत्मविश्वास के साथ कि गांधी जी का स्वदेशी चिंतन एक शाश्वत वैचारिक आंदोलन है, जिसका संबंध समग्र जीवन पद्धति से है। वह कल भी सही था, आज भी सही है और भविष्य में भी सही सिद्ध होगा। इस तरह भारत को पुनः महान बनाया जा सकेगा। यह शुभ है कि भारत की वर्तमान सरकार ने 'स्वदेशी' को अपना प्रमुख एजेंडा घोषित किया है। □□

विकास हेतु स्वदेशी को जरूरी मानते थे श्री गुरुजी



— स्वदेशी संवाद

दिनांक 9-10 सितम्बर, 1952 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा में स्वदेशी पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। श्री गुरुजी से यह पूछा गया कि विदेशी सत्ता की समाप्ति के 5 वर्ष पश्चात इस प्रस्ताव का क्या औचित्य है। श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी विरोध की भावना के कारण लोगों में स्वदेशी वस्तुओं के प्रति सहज आकर्षण था। कांग्रेस द्वारा श्री गाँधीजी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। लोकमान्य तिलक युग में निर्मित स्वतंत्रता आंदोलन की चतुर्सूची योजना का स्वदेशी एक प्रमुख मुद्दा था। डॉ. हेडगेवार ने तो स्वदेशी चेतना को ही संघ के आचार तथा विचारों का अधिष्ठान बनाया था। लेकिन आजादी के पश्चात देश में विदेशी वस्तुओं का अधिक प्रयोग होने लगा है। अतः प्रतिनिधि सभा में पारित प्रस्ताव में स्वयंसेवकों से यह आग्रह किया गया था कि पहले वे स्वयं स्वदेशी का दृढ़ व्रत लें और बाद में लोगों को इस दिशा में प्रवृत्त करें। इस दृष्टि से वर्धा के डॉ. कुमारप्पा को दिनांक 25 सितम्बर, 1952 को श्री गुरुजी ने अपने पत्र में लिखा 'स्वदेशी के विषय में तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रथम स्वराज प्राप्ति का शस्त्र और तदनंतर उसको सुरक्षित एवं उन्नत रखने का आधार स्वदेशी ही है। हम लोगों ने अपने संघ के कार्य द्वारा इस व्रत के आचरण का

आग्रह अधिक तीव्रता से प्रसारित करने का निश्चय किया है।'

स्वदेशी जीवन पद्धति

व्यक्तिगत जीवन में छोटी बातों में भी स्वदेशी जीवन पद्धति का श्री गुरुजी का आग्रह रहता था। यदि गलती से हाथ धोने के लिए उन्हें विदेशी साबुन दे दिया जाता तो राख से हाथ साफ कर वे धीरे से कह देते थे कि विदेशी साबुन से राख मली।

स्वभाषा प्रेम

आंग्ल भाषा के विद्वान होने के बावजूद भी विवाह का निमंत्रण, कार्यक्रम पत्रिका, अभिनंदन संदेश आंग्ल भाषा में छापना भी गुरुजी को अच्छा नहीं लगता था। पुणे के न्याय रत्न धुंडिराज शास्त्री को दिनांक 13-7-55 के पत्र में वे लिखते हैं यज्ञ करने के विषय में आपका पत्रक योग्य समय पर प्राप्त हुआ परन्तु यह अंग्रेजी में लिखा हुआ देखकर विचित्र सा लगा। यज्ञ जैसे पवित्र समारोह का व्यवहार अनार्य में भाषा हो, यह मेरे मन को अच्छा नहीं लगा। इसलिए इस विषय में अत्यन्त आदर और उत्सुकता होकर भी इस समय मुझे लगता है कि इस उपक्रम से संबंध नहीं होना चाहिए। इसलिए क्षमा करें। इसके विपरीत मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पण्डित रवि शंकर शुक्ल द्वारा शासन कार्य हेतु प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार करने पर उनका अभिनंदन करते हुए दिनांक

2-9-1953 को गुरुजी ने अपने पत्र में लिखा "आज से विधिवत आपने मध्य प्रदेश, राज्यशासन में विदेशी भाषा अंग्रेजी को दूर कर हिन्दी तथा मराठी भाषाओं का व्यवहार आपने प्रारम्भ कर दिया, यह जानकर अतीव प्रसन्नता एवं समाधान का अनुभव कर रहा हूँ, इस उत्कृष्ट निर्णय को प्रत्यक्ष में लाने में अनेक कठिनाइयाँ होते हुए भी राष्ट्राभिमान के संतोष के निर्मित उन्हें झेलकर पार करने की दृढ़ता आपने प्रकट की है। इस महान कार्य के लिए मैं अपनी तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से आपका एवं आपके शासकीय सहकर्मियों का हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूँ।"

श्री रजनीकांत मुद्गल ने श्री गुरुजी के हस्ताक्षर मांगते हुए एक पत्र लिखा। उसके उत्तर में उन्होंने लिखा मेरे इस पत्र से आपकी हस्ताक्षर की मांग तो पूर्ण हो जायेगी किन्तु हस्ताक्षर मांगने का आपका यह अंग्रेजी ढंग का उद्योग मुझे उचित नहीं लगता। किसी की स्वाक्षरी या हस्ताक्षर पास रखने से यदि इस व्यक्ति के संबंध में मन में सद्भावना उत्पन्न होती हो, तो उसके तत्त्व तथा गुण अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करना उचित है।

स्वदेशी वेश भूषा

श्री गुरुजी स्वदेशी वेश भूषा के न केवल समर्थक थे बल्कि इसका आग्रह भी करते थे। उनका मानना था कि

यदि हम अपनी पद्धतियों का अवलम्बन करें तो विदेशियों तक में हमारे बारे में सम्मान की भावना निर्मित होती है। इस संबंध में वे अपना स्वयं का अनुभव सुनाते हुए कहते हैं, मैं नागपुर में स्कारिश मिशनरियों द्वारा संचालित एक महाविद्यालय में पढ़ता था। एक बार हम विद्यार्थियों ने पूर्णतः महाराष्ट्रीय पद्धति के भोजन का कार्यक्रम निश्चित किया। इसके लिए प्राचार्य एवं दो यूरोपीय प्राध्यापकों को निमंत्रित किया गया और उन्हें बताया गया कि भोजन धोती पहन कर उधाड़े बदन (कपड़े निकालकर) पीढ़े पर बैठकर करना होगा। प्राचार्य के लिए ईसायत का अहंकार आड़े आ गया और उन्होंने हमारा निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। परन्तु दो वयोवृद्ध प्राध्यापकों ने निमंत्रण स्वीकार किया। उन्होंने ही प्राचार्य को भी तैयार कर लिया। इन तीन यूरोपियों ने धोती पहन कर उधाड़े बदन महाराष्ट्रीय पद्धति से हम लोगों के समान ही हाथों का उपयोग करते हुए भोजन किया। इसी विषय पर श्री गुरुजी ने कहा कि ईश्वर चन्द्र विद्या सागर ने वायसराय कार्यकारी मण्डल की बैठक में जाते समय अंग्रेजी वेशभूषा न पहनने का निश्चय किया। बंगाली ढंग के वस्त्र पहनकर ही वे उपस्थित हुए और उन्हीं को 'कार्यकारी मण्डल की बैठक में सर्वाधिक सम्मान प्राप्त हुआ। उनका स्वागत करने और विदा करने हेतु स्वयं वायसराय मंच से उतर कर आये।

मन में रमे स्वदेशी

श्री गुरुजी यह सोचते थे कि जीवन के अंग-प्रत्यंग में स्वदेशी भावना का प्रकटीकरण हो। अंग्रेजी तिथि तथा सन के स्थान पर भारतीय तिथि तथा संवत् व पाश्चात्य पद्धति के 24 घंटे के दिन के स्थान पर भारतीय पद्धति के 60 घटिकाओं के प्रचलन को वे स्वदेशीकरण का आवश्यक अंग मानते थे। कुछ घड़ी निर्माताओं के

समक्ष इसी प्रकार के घड़ी के निर्माण का विचार भी उन्होंने प्रकट किया था।

मानववाद ही सर्वश्रेष्ठ

श्री गुरुजी समाजवाद, पूँजीवाद की अपेक्षा आर्थिक क्षेत्र में मानववादी थे। समाजवाद एवं पूँजीवाद ने मनुष्य को व्यवस्था के — निर्जीव यंत्र का एक पुर्जा मात्र बना दिया। हमें सम्पूर्ण मनुष्य का विचार करना होगा, जिसके पास हृदय, मस्तिष्क और शरीर तीनों की भूख है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता छिन जाने के कारण सुख के स्थान पर दुख आता चला जायेगा।

गोमाता के प्रति श्रद्धा

गो हत्या निषेध संबंधी एक सभा में गुरुजी ने कहा जिस राष्ट्र का श्रद्धास्थान नष्ट हो जाता है, उस राष्ट्र के अभ्युदय की कामना करना व्यर्थ है। अब हमें यह सोचना है कि सर्व मान्य श्रद्धा केन्द्र कौन सा है? राष्ट्र में राजनीतिक या पंथिक भिन्नता भले ही हो, एक निर्विवाद सत्य है कि गो वंश का नाम लेते ही श्रद्धा की भावना जागृत होती है। अपने हृदय में गोमाता के प्रति श्रद्धागान बजायें। अपने अंतःकरण तथा राष्ट्रजीवन में पराकोटि का तेजस्विता निर्माण करें। इसी संबंध में वे आगे कहते हैं मैं समझता हूँ कि श्रद्धा के विषय में आर्थिक मापदण्ड लगाना अनुचित है। उदाहरण के लिए अपने राष्ट्र का ध्वज है उसे उतारकर तोड़ फोड़ दें तो कौन सी बड़ी हानि हो गयी। लेकिन इन की रक्षा के लिए कितना भी धन जन का मूल्य क्यों न देना पड़े, सर्वथा रक्षणीय है।

उद्योगों का विकेन्द्रीकरण

श्री गुरुजी चाहते थे कि देश में लघु एवं गृह उद्योगों का जाल फैले। वे बड़े औद्योगिक केन्द्रों का पोषण करें जैसे परिदृश्य जापान में हैं। उन्होंने 1949 में ही चेताया था कि इन दिनों औद्योगिकीकरण किसी भी राष्ट्र की

प्रगति का मापदंड बन जाने के कारण विश्व संघर्ष तथा युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है। सच्चे प्रजातंत्र का आधार आर्थिक विकेन्द्रीकरण ही हो सकता है। अतः हमें छोटे-छोटे उद्योगों को ही अपनाना चाहिए। एक संदर्भ में श्री गुरुजी कहते हैं, युद्ध के बाद जापान और पश्चिमी जर्मनी उस समय आर्थिक रूपांतरण के जादू के जीवन्त प्रमाण हैं, जो वहां के नागरिकों के अनुशासित प्रयासों व राष्ट्रभक्ति के उत्साह का परिणाम है। प्रत्येक जापानी के हृदय की धड़कन से एक ही आवाज आती है — 'देश प्रथम'।

ग्रामों की आत्मनिर्भरता

वर्ष 1952 में एक कार्यक्रम में श्री गुरुजी शिवणे ग्राम गये। वहां ग्रामीणों ने मिलकर 1200 फुट लम्बा एक रास्ता तैयार किया था। वहां अपने भाषण में उन्होंने कहा ग्रामीणों ने अपने परिश्रम और स्वावलम्बन से गाँव की एकता की सामर्थ्य से यहां रास्ता बनाकर एक कदम आगे बढ़ाया है। विदेशों से आने वाली सहायता अथवा यंत्रों पर निर्भर रहकर हम अपने देश का विकास कर सकते हैं, लेकिन क्या गाँव के ही लोग स्वयं अपने पैरों पर खड़े हों और अपने गाँव की उन्नति के लिए यत्न करें, यह श्रेष्ठ नहीं है। गाँधी जी कहा करते थे कि मैं विशाल उत्पादन चाहता हूँ परन्तु विशाल जन समूह के द्वारा उत्पादन चाहता हूँ। आज जब वैश्वीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण के नाम पर देश को विदेशियों के हवाले किया जा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में परम पूज्य श्री गुरुजी के स्वदेशी संबंधी विचारों को व्यवहार में लाने की ज्यादा आवश्यकता है। स्वदेशी राष्ट्र भक्ति का एक सशक्त माध्यम है। व्यक्तिगत जीवन, समाज जीवन एवं राष्ट्रजीवन में स्वदेशी का भाव एवं व्यवहार बढ़े, ऐसा आग्रह है। □□

(स्वदेशी पत्रिका से साभार)

स्वदेशी और स्वावलंबन से ही हासिल होगा विकसित भारत का लक्ष्य

— अनिल जोशी



इस समय अपने देश में दो प्रकार के विचार प्रवाह चल रहे हैं। एक यह सोचकर चलता है कि पश्चिम का बनाया पथ ही अपना पथ पड़ेगा। इस विचार के अनुसार प्रगति करने के लिए पश्चिमी विकास पथ अपरिहार्य है। अतः हमें अपनी सारी रचनाएं, संरचनाएं व व्यवस्थाएं इसी विकास पथ के अनुरूप ढालनी चाहिए। इस विकास पथ में तकनीक का विशेष महत्त्व है। यह समूचा विकासपथ तकनीक केन्द्रित ही है। फलतः 'प्रगति के लिए पश्चिम की हर तकनीक से आयात करो' की स्थापना को इस विचार प्रवाह ने प्रतिष्ठित किया है यह आज हमारे देश की अनेकानेक समस्याओं का कारण भी है।

पश्चिम का विकास जिस प्रक्रिया और पद्धति से हुआ है वह शोषण पर आधारित है। यह पश्चिमी विकास पथ यूरोप की परिस्थिति विशेष की उपज है। 16वीं से 18वीं शताब्दी में यूरोप के

अनेक देशों ने एशिया, अफ्रीका व दक्षिणी अमरीका में अपने साम्राज्य स्थापित किए थे। 1670 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारम्भ हुई। इस प्रकार मशीनें बनने लगीं। जो कम श्रम के बदले में विपुल उत्पादन दे रही थी। किंतु इसके लिए तीन चीजों की आवश्यकता थी — 1. विशाल पूंजी. 2. सस्ते में कच्चे माल की प्राप्ति, 3. पक्के माल की खपत के लिए बाजार।

इन साम्राज्यवादी देशों की तीनों आवश्यकताएं उनके उपनिवेशों ने पूरी की। 1760 के पहले तक बैंक ऑफ इंग्लैंड में ज्यादा पैसा नहीं था। उस समय इंग्लैंड में पैसा आने का एक मात्र स्रोत था समुद्र में होने वाली लूट। इंग्लैंड के समुद्री लूटेरे जो भी लूटते थे उसका एक भाग सरकारी खजाने में जाता था। किंतु 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज बहुत बड़ी मात्रा में लूट का धन इंग्लैंड ले गए। उन्होंने जो पक्का

माल बनाया वह उन दिनों की तकनीक की स्थिति के कारण बड़ा घटिया दर्जे का होता था कि उसकी तुलना में यूरोप का माल टिक नहीं पाता था और यूरोप भर में, खासकर इंग्लैंड के बाजारों में भारतीय माल की काफी मांग थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने सोचा कि जब तक भारत में उत्पादन की जो विकेन्द्रित पद्धति है, जिसके माध्यम से गांव गांव में विभिन्न वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन होता था, जब तक इसको बंद नहीं किया जाता तब तक भारतीय बाजार उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए अत्यंत निष्ठुर होकर उन्होंने यहां के स्थानीय उद्योगों को नष्ट किया। और उस बाजार को जिसका माल दुनिया भर में जाता था विदेशी माल से भर दिया और यहां की जो मूल अर्थव्यवस्था थी, वह चौपट हो गई।

भारतीय ग्रामीण व कुटीर उद्योगों के नष्ट होते ही हम औद्योगिक माल के लिए विदेशियों पर निर्भर हो गए। यही हाल अन्य गुलाम देशों का भी हुआ। शोषण पर आधारित यह व्यवस्था उसी अवस्था में सफल हो सकती थी जबकि शोषण करने के लिए कोई उपनिवेश विद्यमान न हो।

इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 1945 में महात्मा गांधी ने नेहरू जी से कहा था कि हमें अपने देश के लिए नया विकास पथ बनाना चाहिए जो ग्राम आधारित हो, अल्प पूंजी पर चलने

वाली स्थानीय मशीनों के द्वारा तैयार किया जाए और जो प्रकृति से सुसंगत हो। किंतु जिन नेहरू को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, उनकी सारी शिक्षा दीक्षा इंग्लैण्ड में होने के कारण उन्होंने गांधी जी के सुझाव को नहीं माना और जो पश्चिम का विकास पथ था उसको ही स्वीकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी से बाकायदा प्रस्ताव पारित करवाया था।

पश्चिमी विकास पथ के दो पक्ष थे — एक, अमरीका का पूंजीवादी रास्ता दूसरा सोवियत रूस का राजसत्ता केन्द्रित साम्यवादी रास्ता। समाजवाद के नाम पर नेहरू ने इन दोनों का मिला जुला स्वरूप 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' को स्वीकार किया और समाजवादी के नाम पर यही व्यवस्था 1985 तक चलती रही। 1985 में अचानक पुराना रास्ता छोड़ दिया और एकदम पूंजीवादी रास्ता पकड़ लिया। दोनों ही समय कांग्रेस में कोई खुलकर चर्चा नहीं हुई।

सोवियत संघ का मॉडल वहां भी खत्म हुआ यहां भी खत्म हुआ। और जिस पूंजीवाद के रास्ते को अब अपनाया है वह शोषण पर आधारित है। पश्चिमी विकास पथ का लाभ मात्र 15 प्रतिशत जनता को ही मिल रहा है वह भी शहरों व कस्बों में रहने वालों को। गांवों और वनांचल की कीमत पर से समृद्ध हुआ अर्थात् गांव व जंगल का शोषण करके समाज का एक छोटा वर्ग इस विकास पथ से लाभान्वित हुआ। आज विकास के नाम पर जब कोई बांध बनता है तो उसका लाभ जितनी संख्या में लोगों को मिलता है उसके अनुपात में थोड़ी संख्या में उससे कई गुनी संख्या में विस्थापित होने वालों का जीवन स्तर और भी दयनीय बन जाता है।

आज भारत में यह संघर्ष चल रहा है। कुछ लोग इस पश्चिमी विकास पथ को ही उदासीकरण व भूमंडलीकरण के नाम पर जारी रखना चाहते हैं। जो नए

आज पश्चिम के देशों में बौद्धिक धरातल पर पश्चिमी विकासपथ के मॉडल को ही चुनौती दी गई है। समृद्ध देशों की 20 प्रतिशत जनसंख्या दुनिया के 80 प्रतिशत संसाधनों का स्वयं उपभोग करती है।

संदर्भों में विकासशील देशों के कच्चे माल व बाजार पर कब्जा करने की विकसित देशों की कुत्सित योजना का ही एक अंग है। विश्व बैंक, विश्व मुद्राकोष और विश्व व्यापार संगठन ये सभी ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा विकाशील देशों के कच्चे माल को हस्तगत करके पक्के माल अर्थात् विकसित देशों के उत्पाद, उनके ब्रांड और उनकी तकनीक थोपने वाले उपकरण विकासशील देशों के बाजारों में बेचकर अपनी समृद्धि के स्तर को बनाए रखने का प्रयास है। इन लुभावने नारों में अधिकांश विकासशील देश आ जाते हैं और उनके अर्थशास्त्री भी जो कि उसी पश्चिमी शिक्षा पद्धति की उपज हैं। वे कोई नई बात, कोई नया रास्ता सोचने की हिम्मत ही नहीं कर पाते।

आज पश्चिम के देशों में बौद्धिक धरातल पर पश्चिमी विकासपथ के मॉडल को ही चुनौती दी गई है। समृद्ध देशों की 20 प्रतिशत जनसंख्या दुनिया के 80 प्रतिशत संसाधनों का स्वयं उपभोग करती है। तो इससे समतामूलक विश्व कैसे तैयार हो सकेगा। एक न्याय-युक्त वितरण विश्व के सब देशों में हो तो यह तभी संभव है जब पश्चिमी देश अपने भौतिक उपभोग के वर्तमान स्तर को कुछ नीचे लाएं।

इसके लिए एक दूसरी बाधता भी सामने खड़ी है और वह है प्रकृति के भंडार का तीव्रगति से क्षरण और भयावह ढंग से फैल रहा प्रदूषण। इस परिस्थिति ने दूरदर्शी चिंतकों के मन में विश्व के भविष्य के संबंध में आशंका उत्पन्न की है। इसलिए विश्व के विभिन्न देशों में वैकल्पिक विकास पथ की खोज चल रही है। आज का विकास पथ केन्द्रीकृत, शहर आधारित, भारी पूंजी खाने वाली और ऊर्जा का अत्याधिक भक्षण करने वाली व बेकारी बढ़ाने वाली व प्राकृतिक संतुलन का विनाश करने वाली पद्धति है। इसके स्थान पर विकेन्द्रीकृत, ग्रामाधारित अल्पपूंजी व ऊर्जा प्रयोग करके अधिक रोजगार देने वाली, प्रकृति सुसंगत व्यवस्था का विकास आवश्यक हैं।

इस विकल्प की खोज ही स्वदेशी आंदोलन हेतु है। इस प्रक्रिया में पुरानी व्यवस्था से लाभान्वित होने वाले लोगों के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे जिस सुविधा के आदी हो गए हैं वह उनसे छिन जाएगी। शोषण व आर्थिक लूट द्वारा साम्राज्य खड़ा करने वाले बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रायोजित इस प्रबल प्रतिरोध का स्वल्प साधनों वाले स्वदेशी आंदोलन को सामना करना पड़ेगा। इस लिए लड़ाई असमान होते हुए भी लोक जागरण और लोक प्रशिक्षण के माध्यम से इसमें विजय प्राप्त की जा सकती है। अतएवं आज वैकल्पिक विकास मार्ग पर दृढ़ विश्वास रखते हुए उसकी सफलता के लिए एक लम्बे संघर्ष के लिए अपनी कमर कसनी होगी। आज जिस तरह पश्चिम के पहरेदार ट्रेड टैरिफ के नाम पर गरीब और विकासशील देशों के विरुद्ध आर्थिक कठिनाईयां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एकजुट संघर्ष से ही रास्ता निकलेगा। स्वदेशी स्वावलंबन से पूर्ण आत्मनिर्भरता तथा विकसित भारत का लक्ष्य हासिल होगा। □□

(लेखक वैश्विक हिंदी परिवार के अध्यक्ष हैं।)

ग्राम स्वास्थ्य सेवाएं समग्र बनें

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के साथ-साथ 'सबका स्वास्थ्य' के मुद्दे पर प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आरोग्य जीवन के लक्ष्य को हासिल करने हेतु गरीबों एवं बुजुर्गों को 'आयुष्मान' के तहत लाया गया है। 'आयुष्मान' कार्ड धारक देश के किसी भी अस्पताल में पांच लाख रुपये तक का ईलाज करा सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में एम्स जैसे अस्पतालों की स्थापना के साथ-साथ सरकार ने स्वस्थ भारत मिशन के तहत अपना बजटीय प्रावधान का आकार भी बड़ा किया है। सरकार का प्रयास है कि स्वास्थ्य सुविधाएं शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी समान रूप से पहुंचाई जा सके।

ग्राम स्वास्थ्य सेवाओं को सब तक सामुदायिक सहयोग से पहुंचाने का उद्देश्य सदा हमारी प्राथमिकता रहा है, पर ये सेवाएं कितने समग्र रूप में आगे जा सकेंगी, यह बहस का मुद्दा बनता रहा है। पहले सभी स्वास्थ्य समस्याओं के समग्र रूप में समाधान पर अधिक जोर दिया गया पर अनेक विकासशील देशों ने जब इसे व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया तो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के कारण उन्हें लगा कि कुछ प्राथमिकताओं को चुनकर उन्हें अधिक महत्त्व देना होगा।

इस स्थिति में ऐसे रोगों या स्वास्थ्य समस्याओं को चुना गया जिनमें कमी लाकर अधिक जीवन बचाए जा सकते थे। ऐसी प्राथमिकताओं का औचित्य समझते हुए भी अनेक स्वास्थ्यविद् ने स्वास्थ्य और विशेषकर ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी एक समग्र सोच विकसित करने की जरूरत पर ध्यान दिलाना जारी रखा क्योंकि सही अर्थों में और टिकाऊ तौर पर स्वास्थ्य सुधार इस समग्र सोच से ही संभव है। ऐसी समग्र सोच में जहां सभी स्वास्थ्य समस्याओं का समावेश होता है, वहां स्वास्थ्य को नजदीकी तौर पर स्वच्छता और पोषण से जोड़ कर भी देखा जाता है। स्थानीय स्थितियों के अनुसार बेहतर पोषण के सुझाव देना तो अपेक्षाकृत सरल कार्य है, पर कठिनाई वहां आती है, जहां स्थानीय समुदायों के अनेक परिवारों (जैसे भूमिहीन और सबसे निर्धन परिवारों) में उस पोषण को प्राप्त करने की आर्थिक क्षमता ही नहीं होती है। इस स्थिति में अनेक स्वास्थ्य कार्यक्रमों ने न्यायसंगत व्यापक मांग भी उठाई हैं। फिलहाल, इतना प्रयास तो वे कर ही सकते हैं कि इन परिवारों के आजीविका सुधार के कुछ व्यापक प्रयासों से जुड़ें। इसमें भी अधिक सुगम प्रवृत्ति यह पाई जाती है कि सब्जी का छोटा सा बगीचा लगा कर या मुर्गी पालन से पोषण को कुछ बेहतर कर लिया जाए। इससे कुछ सुधार तो अवश्य होता है पर यदि अन्य प्रतिकूल स्थितियों से आजीविका बिगड़ रही है, तो फिर कुल मिला कर स्थिति विकट ही बनी रहती है।

अतः स्वास्थ्य कार्यक्रम में समग्रता पर जोर देने की आवश्यकता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि आजीविका सुधार के प्रति भी समग्र दृष्टिकोण ही अपनाया जाए। दूसरी ओर, कुछ अन्य व्यक्ति कहते हैं कि इस तरह तो जिम्मेदारी और कार्य बहुत बढ़ जाएंगे। यहां एक समाधान यह हो सकता है कि यदि स्वास्थ्य कार्यक्रम बहुत सी आजीविका जिम्मेदारियों को संभाल न भी सकें तो कम से कम इस बारे में स्पष्ट सोच अवश्य बना लें कि आजीविका सुधार की किस दिशा में जाना है, और किन गलतियों से बचना है।



ग्राम स्वास्थ्य सेवाओं को सब तक सामुदायिक सहयोग से पहुंचाने का उद्देश्य सदा हमारी प्राथमिकता रहा है, पर ये सेवाएं कितने समग्र रूप में आगे जा सकेंगी, यह बहस का मुद्दा बनता रहा है।

— डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र



भारतीय ग्रामीण स्थिति को देखें तो प्रायः अनेक स्थानों पर छोटे किसानों और भूमिहीनों से न्याय, प्राकृतिक खेती, जल और मिट्टी संरक्षण, गांववासियों में बढ़ते सहयोग, वनों की रक्षा और स्थानीय प्रजाति के वृक्षों में वृद्धि, जैव-विविधता और परंपरागत बीजों की रक्षा, रचनात्मक रोजगार सृजन और गांव समुदाय की बढ़ती आत्मनिर्भरता का मॉडल अनुकूल और प्रेरक है। यह सोच बहुत कुछ स्वतंत्रता आंदोलन और विशेषकर महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की सोच के अनुकूल है। इस सोच पर आगे बढ़ने में कोई महंगा खर्च नहीं है अपितु किसानों के खर्च और कर्ज कम होंगे। इसके अतिरिक्त यह सोच पर्यावरण की रक्षा और टिकाऊ विकास के लिए बहुत भी अनुकूल है। इन दिनों जलवायु बदलाव के खतरे को कम करने और उसका सामना करने की क्षमता को बढ़ाने (मिटीगेशन और एडॉप्टेशन) की अधिक चर्चा है और इसके लिए धन और बजट भी उपलब्ध है। यह सोच इस दृष्टि से भी बहुत अनुकूल है और इसे अपना कर जलवायु बदलाव के खतरे को कम करने और इसका सामना करने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी बढ़ा जा सकता है।

समाज-सुधार के अनेक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। इनमें स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि निरंतरता से शराब, तंबाकू, गुटके, ड्रग्स, गांजा आदि के विरुद्ध जन-अभियान चला

कर इनका उपयोग कम से कम किया जाए। इसके लिए सभी गांवों में महिलाओं के नेतृत्व में नशा-विरोधी समिति बनानी चाहिए और इसका कार्य निरंतरता से चलना चाहिए। इसके अतिरिक्त समग्र स्वास्थ्य के लिए समाज-सुधार के अनेक अन्य पक्ष भी महत्वपूर्ण हैं जैसे गांववासियों का आपसी सहयोग बढ़ाना, महिलाओं की समानता और ग्रामीण कार्यों में अधिक जिम्मेदारी, बाल विवाह को रोकना, शिक्षा विशेषकर लड़कियों की शिक्षा में सुधार, जुए और अन्य कुरीतियों पर रोक। ये विभिन्न समाज-सुधार अपने आप में बहुत सार्थक हैं पर साथ ही समग्र स्वास्थ्य प्राप्त करने के उद्देश्य में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अतिरिक्त यदि गांव में अहिंसा और अमन-शांति की सोच को प्रतिष्ठित और मजबूत किया जाए तो इससे भी समग्र स्वास्थ्य प्राप्ति में मूल्यवान योगदान मिल सकता है, और विशेषकर बढ़ते मानसिक तनाव और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में बहुत कमी आ सकती है। हालांकि अमन-शांति पर अधिक चर्चा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में होती है, पर हकीकत तो यह है कि दैनिक जीवन में जो हिंसा है या हिंसक सोच है, वह अनेकानेक समस्याओं और दुख-दर्द के मूल में है। वैसे तो स्थितियों में बहुत भिन्नता हो सकती है, पर अनेक गांवों में इनमें से अनेक स्थितियां महत्वपूर्ण स्तर पर मौजूद हैं—महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा, बहुत समय

से चल रहे झगड़े और मुकदमेबाजी, जाति और धर्म आधारित भेदभाव और हिंसा, भूमि-विवाद, तरह-तरह का शोषण और उससे जुड़ी हिंसा, गुटबाजी और लठैतबाजी, हथियारों की बढ़ती उपस्थिति और अपराधी गतिविधियों की वृद्धि, संसाधनों की नियोजित लूट और इसके लिए हिंसा का उपयोग।

ये सभी प्रवृत्तियां जहां अपने आप में हानिकारक हैं, इनके कारण मानसिक तनाव, अवसाद और निराशा, बुनियादी जरूरतों से वंचित होना, भूख और कुपोषण, नशे का प्रचलन आदि समस्याएं बढ़ जाती हैं। दूसरी ओर, यदि दैनिक जीवन में न्याय आधारित अमन-शांति और अहिंसा स्थापित करने और आधिपत्य की प्रवृत्ति को दूर करने के प्रयास किए जाएं तो समग्र स्वास्थ्य के उद्देश्य को प्राप्त करने में बहुत सहायता मिल सकती है। घरेलू हिंसा को न्यूनतम कर पाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। समग्र स्वास्थ्य की यह व्यापक सोच ग्रामीण संदर्भ में विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण है, इस सोच को अपनाते हुए न केवल पोषण की मात्रा बढ़ाई जा सकती है अपितु यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्राकृतिक खेती से प्राप्त विभिन्न खाद्यों की स्वास्थ्य की दृष्टि से गुणवत्ता कहीं बेहतर होगी। दूसरी ओर, इस समग्र सोच के अनेक पक्ष ऐसे हैं, जो ग्रामीण या शहरी या किसी भी क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पहली नजर में लग सकता है कि इस तरह की सोच अपनी व्यापकता के कारण बहुत सी जिम्मेदारियों को बढ़ा सकती है, पर इस समग्रता में इतनी रचनात्मकता है, और इसके उद्देश्य इतने खूबसूरत हैं कि इस राह पर चलने में कोई बोझ प्रतीत नहीं होगा अपितु साथ चलते हुए निरंतर प्रेरणादायक माहौल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सच मानें तो यही स्वदेशी का मूल भाव है। □□

कृषि एवं स्वदेशी दृष्टि

भारतीय संस्कृति में कृषि की बहुत महत्ता है। दशावतारों में से एक भगवान श्री बलराम हल एवं मूसल धारण किया करते थे और परब्रह्म परमात्मा स्वयं श्रीकृष्ण हल मूसलधारी कृषक श्रीबलराम के रूप में अवतरित हुए थे। भारतीय परम्परा के गहनतम विद्वान राजा जनक अपने हाथ से हल चलाते थे। हल लेकर यज्ञार्थ पृथ्वी का कर्षण करते हुए ही राजा जनक को सीता जैसी पुत्री प्राप्त हुई थीं और, कृषि के माध्यम से प्राप्त पृथ्वी-पुत्री जानकी (सीता) से विवाह कर पुरुषोत्तम श्रीराम संपूर्ण हुए थे। अपने कलियुग में श्री गुरुनानक ज्ञान के अनुसंधान में अनेक बार विश्वाटन करते रहे और अंततः ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त करने के उपरांत वे करतारपुर में बसकर कृषि करने लगे। वहां करतारपुर में कृषि करते हुए श्री गुरुनानक ने सिक्ख संप्रदाय की स्थापना की। उनके साथ मिलकर कृषि करते हुए ही भाई लहना गुरुपद को प्राप्त हुए और इस प्रकार सिक्ख गुरु परंपरा का सूत्रपात हुआ। यह स्वाभाविक ही है कि श्रीगुरुनानक के अनुयायी सिक्ख आज भी देश के सर्वोत्तम कृषकों में गिने जाते हैं।

महाभारत के शांतिपर्व में युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश देते हुए भीष्म पितामह उन्हें बताते हैं कि 'निश्चय ही कृषक राजा का बोझ अपने कंधों पर उठाते हैं। कृषक ही राष्ट्र में अन्य सबका भरण करते हैं। कृषकों के दिए अन्न से ही देव, पितर, मनुष्य, गंधर्व, राक्षस, पशु एवं पक्षी सब—के—सब जीवन धारण करते हैं। अतः राजा को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कृषक पीड़ित हों।' इसी प्रकार सभापर्व में नारदमुनि राज्य की व्यवस्था के विषय में युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हुए कृषि के प्रति विशेष आग्रहपूर्वक जानना चाहते हैं कि 'तुम्हारे राज्य में किसान संतुष्ट तो हैं? राज्य के सब भागों में खेतों की सिंचाई के लिए विशाल तड़ाग तो बना दिए गए हैं न? ये सब तड़ाग जल से परिपूर्ण तो रहते हैं? कहीं कृषि मात्र वर्षा के जल पर निर्भर तो नहीं? खेती को मात्र दैव पर ही तो नहीं छोड़ दिया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे राज्य के कृषक अन्न अथवा बीज के अभाव में कष्ट पा रहे हों? ऐसी स्थिति में तुम उन पर अनुग्रह कर एक प्रतिशत व्याज पर ऋण तो दिया करते हो न?' आदि।

वाल्मीकि रामायण में जब भरत श्रीराम को मिलने चित्रकूट जाते हैं तो कोशल देश की सुव्यवस्था के प्रति चिंतित श्रीराम भरत से कृषि संबंधी ऐसे ही अनेक प्रश्न पूछते हैं। वे जानना चाहते हैं कि कोशल देश के तड़ाग जल से परिपूर्ण तो हैं, कृषि मात्र बरसा पर तो निर्भर नहीं हो गयी, देश कृषि में समर्थ स्वस्थ पशुओं से परिपूर्ण तो है, आदि। और अंत में वह भरत से पूछते हैं कि 'कृषि एवं गोरक्षा ही जिनका जीवन है। ऐसे सब लोग तुम्हारे विशेष प्रीतिपात्र तो हैं न? कृषि एवं गोरक्षा का अवलम्बन लेकर ही यह लोक सुख—समृद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए इन कार्यों में लगे लोगों का तुम्हें विशेष सावधानीपूर्वक भरण करना चाहिए। इनके दृष्टि की प्रति एवं अनिष्ट के निवारण के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।'

भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में कृषि का ऊँचा महत्व रहा है। अतः कृषि के प्रति स्वदेशी दृष्टि का पहला आयाम तो यही है कि देश की नीति में कृषि को वैसा ही उच्च स्थान प्राप्त हो जैसा भारतीय परंपरा में उसे दिया गया है।

महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के समय जब स्वदेशी का आंदोलन चलाया था तो खादी को स्वदेशी का मूलाधार बनाया था। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ वर्ष पूर्व भविष्य के भारत पर विचार करते हुए उन्होंने अनेक बार स्पष्ट किया था कि खेती पर वे इसलिए आग्रह नहीं



आज भारत में प्रति व्यक्ति अन्नोत्पादन विश्व के प्रायः अन्य देशों की तुलना में कम है। अतः स्वदेशी कृषि का पहला लक्ष्य तो देश में अन्नोत्पादन की मात्रा को शीघ्रातिशीघ्र बढ़ाना चाहिए।
— शिवनंदन लाल

कर पाये क्योंकि खेती के उन्नयन के लिए राज्य का सहयोग आवश्यक होता है। विदेशी राज तो खेती में होने वाले किसी सुधार का लाभ कृषकों तक पहुंचने ही नहीं देता।

गांधी जी ने कहा था कि खादी हमें उतना आगे नहीं ले जा सकती जितना हम सोचते रहे हैं। तो हमें कृषि जैसे किसी अन्य मूलभूत व्यवसाय को अपनाने पर विचार करना चाहिए। मेरा तो प्रारंभ से ही यह पक्का विश्वास रहा है कि कृषि ही इस देश के लोगों के भरण-पोषण का स्थायी एवं अचूक साधन बन सकती है।

विदेशी प्रशासन के अधीन खेती को भारत की जागृति एवं भारत के गांवों की उन्नति का मूलाधार बनाने में महात्मा गांधी हिचक रहे थे। परंतु स्वतंत्र भारत में राष्ट्र-निर्माण का मूलाधार तो उनके अनुसार कृषि को ही होना था।

भारत के लोकजीवन में कृषि के स्थान पर विशेष चिंतन हुआ है। परंतु जहां ऐसे गहन चिंतन की परंपरा नहीं है वहां भी कृषि को आर्थिकता का मूल तो माना ही जाता है। एडम स्मिथ का समस्त चिंतन स्वदेशी के विपर्याय-सा है। परंतु उनका भी मानना है कि अन्न उत्पादन की प्रचुरता के बिना किसी समाज की अर्थव्यवस्था का प्रारंभ ही नहीं होता। वे कहते हैं कि “जब अन्न पर्याप्त होता है तभी अन्य वस्तुओं का मूल्य लगना शुरू होता है। जहां अन्न ही पर्याप्त न हो वहां तो रोटी के टुकड़े के बदले में सोना प्राप्त किया जा सकता है।

एशिया के जिन देशों को प्रायः हमारे साथ-साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उनमें से अधिकतर ने राष्ट्र निर्माण में कृषि की मौलिक स्थिति को समझा है। इण्डोनेशिया, थाइलैंड, ताईवान, दक्षिण कोरिया में भी कृषि ही राष्ट्रीय विकास का ध्येय बना। कृषि के मार्ग पर चलकर ही औद्योगीकरण की ओर बढ़े।

भारतीय संस्कृति में अन्न को ब्रह्म की संज्ञा दी गयी है। उपनिषद् का आदर्श वाक्य है: अन्नं बहुकुर्वीत। सब प्रकार से अन्न का बाहुल्य करो।

आज वैश्वीकरण के युग में राष्ट्र विकास का मूलाधार कृषि को बनाना और आवश्यक हो गया है। कृषि के उन्नयन में किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को वह दृढ़ता प्राप्त होती है जो उसे समर्थ बनाती है। चीन ने इस मूल सिद्धांत को समझते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के खुला छोड़ने से पूर्व अपनी कृषि को बढ़ाया। ऐसे ही वियतनाम ने अपना सारा ध्यान कृषि की वृद्धि पर केंद्रित किया।

आज भारत में प्रति व्यक्ति अन्नोत्पादन विश्व के प्रायः अन्य देशों की तुलना में कम है। अतः स्वदेशी कृषि का पहला लक्ष्य तो देश में अन्नोत्पादन की मात्रा को शीघ्रातिशीघ्र बढ़ाना चाहिए। वस्तुतः राज्य को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि कृषक अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन करने की ओर प्रवृत्त हो।

भारतीय संस्कृति में अन्न को ब्रह्म की संज्ञा दी गयी है। उपनिषद् का आदर्श वाक्य है: अन्नं बहुकुर्वीत। सब प्रकार से अन्न का बाहुल्य करो। अन्न संबंधी इस भारतीय परंपरा को परिभाषित करते हुए ही जगद्गुरु श्री शृङ्गेरी आचार्य श्रीमद्भारती तीर्थ महास्वामी ने कहा था कि अन्न का सम्यक् उत्पादन एवं विनियोग किए बिना कोई राष्ट्र अन्यान्य विषयों में परिश्रमशील होने लगे, यह तो ऐसे हुआ जैसे कोई व्यक्ति उपनयन किए बिना ही वाजपेय आदि यज्ञों का संपादन करने का प्रयास करने

लगे। यह असंभव है।

भारतीय परंपरा में अन्न के उत्पादन का जैसा महत्व है उससे कहीं अधिक अन्न के सम्यक् विभाजन का है। भारत के सामान्य -जन आज भी ऐसा मानते हैं कि जहां अन्न का सम्यक् विभाजन नहीं होता वहां सम्यक् उत्पादन भी नहीं हो पाता। रामचंद्र जी अपने वनवास के दिनों में लक्ष्मण के साथ अन्न का अनुसंधान करते हुए घूम रहे थे। तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि देखो यह सारी पृथ्वी धन-धान्य से परिपूर्ण है। परंतु हमें भोजन प्राप्त करने के लिए दौड़-धूप करनी पड़ रही है। इस समस्या का समाधान करते हुए आगे वे लक्ष्मण को बताते हैं कि पूर्वकाल में हमने पर्याप्त अनुदान नहीं किया होगा, तभी हमें अन्न के लिए इस प्रकार भटकना पड़ रहा है। क्योंकि यह नियम है कि अन्न तो उतना ही प्राप्त होता है जितना अन्यो को देकर अर्जित कर लिया जाता है। और, सम्यक् विभाजन से जो अर्जित नहीं कर लिया गया उसे तो न विद्या से और न पौरुष से पाया जा सकता है।

जिस नियम का अतिक्रमण श्रीरामचन्द्र जी से संभव नहीं था, उसका सामान्यजन कैसे अतिक्रमण करेंगे? इसीलिए भारत के धर्मशास्त्रों की यह स्पष्ट व्यवस्था है कि किसी गृही को अन्न का उपभोग करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सब जीव, सब मानव, पशु, पक्षी और देव, गंधर्व, पितरादि सब तृप्त हो चुके हैं। सबको अपना-अपना भाग प्राप्त हो चुका है। महाभारत में कहा गया है कि जिस राजा के राज्य में किसी एक भी जीव को भूख की पीड़ा सहने को विवश होना पड़ता है, उस राजा का जीना व्यर्थ है। ऐसी परम्परा वाले देश में स्वदेशी कृषि नीति निश्चय ही अनाज के सम्यक् संविभाजन पर आधारित होगी। □□

स्वदेशी कृषि एवं गोरक्षण

— वरुण कुमार पाण्डेय



भौतिकी के आधुनिक काल के महानतम वैज्ञानिक एलबर्ट आइन्स्टीन वैज्ञानिक के साथ-साथ एक भविष्यद्रष्टा भी थे। उन्होंने भारत को आगाह करते हुए कहा था कि उसे अपनी कृषि के लिए रासायनिक खाद तथा ट्रैक्टर आधारित पद्धति नहीं अपनानी चाहिए। उनका मानना था कि इस पद्धति से भूमि की उर्वरा शक्ति का क्षय होता है। उनका अमरीका के विषय में यह आँकलन था कि वहाँ की धरती को उर्वरा शक्ति आने वाले चार सौ वर्षों में समाप्त हो जाएगी। दूसरी ओर देखा जाए तो भारतीय धरती की उर्वरा शक्ति हजारों वर्षों से चली आ रही कृषि पद्धति के कारण अक्षय बनी रही है। आइन्स्टीन ने यह भी कहा था कि जिस धरती पर ट्रैक्टर व रासायनिक पद्धति से कृषि होगी वहाँ एक हजार वर्ष बाद घास का तिनका तक न उग सकेगा। स्वदेशी को श्रेष्ठता का इससे बढ़कर प्रतिपादन मिलना लगभग असंभव ही है।

भारत के लिए कृषि का सनातन काल से चला आ रहा स्वदेशी प्रतिरूप ही उत्तम है। स्वातन्त्र्योत्तर भारत के महान स्वदेशी विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय कृषि के सर्वांगीण विकास की बात करते थे। पश्चिमी सोच जिसमें कृषि को उद्योग माना जाता है, के विपरीत उनका कहना था कि कृषि का विकास ऐसा होना चाहिए कि वह अधिकतम उद्योगों का आधार बन सके। देश का विराट औद्योगीकरण बिना

व्यापक और सक्षम कृषि के संभव नहीं है और वह कृषि बिना धरती की उर्वरता अक्षय बनाए रखे नहीं हो सकती। पश्चिमी प्रकार को ट्रैक्टर आधारित व रासायनिक कृषि भूमि की उर्वरता को लील रही है अतः गोवंश आधारित सनातन काल से चली आ रही कृषि ही सही विकल्प है। इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस प्रकार की कृषि में नवीनता या आधुनिकता के लिए कोई संभावना नहीं है। इसके ठीक विपरीत इसमें नवीन शोध और क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक लोच कहीं अधिक मात्रा में उपलब्ध है। चाहे विषय कृषि यंत्रों का हो या खादों का अथवा कीटनाशकों का। पारंपरिक कृषि में शोध और नवाचार अपनाने की असीम संभावनाएँ हैं।

गोवंश आधारित कृषि के लिए बड़ी समस्याओं में एक समस्या चारे की है। देश में चारे की अनुपलब्धता के कारण कृषक यह सोचने पर बाध्य हो जाता है कि खड़ा ट्रैक्टर चारा तो नहीं माँगता। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी के वैज्ञानिकों ने इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षिक करते हुए लिखा है कि देश में 55 प्रतिशत पशु चारे के अभाव में रहते हैं। चारे की इस कमी के कारण पशु कुपोषण के शिकार हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप वे अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता प्राप्त नहीं कर पाते। इस कारण उन्हें रखना या उन पर आधारित कृषि से देश का पेट

भरना कठिन हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत में उपलब्ध जैव विविधता के कारण चारे के इतने स्रोत उपलब्ध हैं कि यदि उनका समुचित उपयोग किया जाए तो चारे की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है।

यदि इस समस्या का समाधान कर लिया जाए तो सनातन काल से चली आ रही गोवंश आधारित स्वदेशी पद्धति की कृषि विकल्प नहीं अपितु मुख्य धारा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती है। गोवंश और उस पर आधारित अर्थव्यवस्था के बहुत से सूत्र अब भी उपलब्ध हैं। गाय के साथ भारतीय मानस का जुड़ाव हर स्तर पर हर समय रहा है। जहाँ भारतीय परंपरा ने गऊ को माँ कहकर समाज में उसे प्रतिष्ठित किया है। वहीं उसके आर्थिक पक्ष से भी वह कभी अनभिज्ञ नहीं रहा। गाय की अर्थव्यवस्था धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुषार्थ का हिस्सा है। वहाँ कोरे स्वार्थ की अंधी अर्थरचना नहीं है।

भारतीय लोकजीवन में इस धारणा को परखने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण एक मिथक के रूप में मिलता है। कहा जाता है कि मनुष्य मृत्यु के उपरांत गाय को पूँछ पकड़कर वैतरणी नामक एक नदी को पार करता है। यह बड़ा ही रोचक किन्तु (मोरल) नैतिक मिथक है। क्योंकि गाय और गोवंश ही हिंदू अर्थव्यवस्था का सदा से आधार रहा है इसीलिए वही व्यक्ति की संपन्नता का

भी आधार था। सम्पन्नता के साथ हर व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपनी अगली पीढ़ी को सम्पन्नता देकर संतोष के साथ विदा होना है। यह बैतरणी और कुछ नहीं अपितु किसी को मृत्यु के उपरांत उसके बच्चों में संपत्ति वितरण की सामान्य प्रक्रिया है और गाय जो स्वयं संपत्ति और संपन्नता के निर्माण की अधिष्ठात्री माता है वहीं व्यक्ति को मृत्यु के बाद वितरण की बैतरणी को संतोषपूर्वक पार लगा देती है। यही इस मिथक का सरल सा वास्तविक रूप रहा है।

अंग्रेजों द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था छिनभिन्न करने में जो सबसे बड़ी हानि भारत की हुई वह इसमें आंकना तो सरल है कि वे यहाँ से कितनी संपत्ति लूट कर ले गए किंतु उससे बड़ी हानि तो उन्होंने भारत की अर्थरचना को समाप्त करके की। उसका आकलन असंभव है। किंतु अभी भी भारतीय स्वदेशी अर्थरचना के कुछ सूत्र उपलब्ध हैं। उन पर आगे शोध और फिर उसका प्रयोग देश के अर्थजीवन में हो तभी भारत की संपन्नता लौट सकती है।

इस दिशा में देशभर में अलग-अलग स्थानों पर शोध और परीक्षण चल रहे हैं जिनके आशातीत सकारात्मक परिणाम निकल रहे हैं। कहा जाता है कि दूध देने की आयु समाप्त होने के बाद या दूध न दे सकने वाली गायों को मारना उचित है क्योंकि उनसे कोई आर्थिक लाभ तो है नहीं, दूसरे जो लोग गोमांस भक्षण करते हैं उन्हें सस्ता भोजन प्राप्त हो जाता है। किन्तु वास्तव में यह तथ्य वास्तविकता के विपरीत है। यदि गाय दूध न भी देती हो तो भी उसके गोबर से ही बहुत बड़ी मात्रा में जैविक खाद की प्राप्ति हो जाती है। एक किलो गोबर से बीस किलो जैविक खाद तैयार की जा सकती है। यदि एक परिवार में गोवंश जो दूध न भी है रहा हो और दिन भर में दस

किलोग्राम गोबर उपलब्ध कराता हो तो प्रतिदिन दो सौ किलोग्राम जैविक खाद या वर्ष भर में 14.5 एकड़ भूमि के लिए जैविक खाद उत्पन्न करा सकता है। ज्ञातव्य है कि इतने ही क्षेत्र में लगायी जाने वाली रासायनिक खाद न केवल कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता घटाती है अपितु पर्यावरण विशेषतः भूजल का भी नाश करती है।

यह तो शोध पर आधारित आंकलन है किंतु इस समय भी पशुधन मानव संसाधनों के बाद देश का सबसे बड़ा संसाधन है। आज भी भारत में रेलगाड़ियों से अधिक माल दुलाई बैलगाड़ियों द्वारा होती है। यह विडम्बना ही है कि अबतक देश में पशु संसाधन विकास मंत्रालय नहीं बना जबकि रेल जोकि पशुओं द्वारा प्रदत्त कई सेवाओं में से मात्र एक से भी कम उत्पादकता देश के लिए देती है उसके लिए अलग मंत्रालय है। पशुधन से देश की 5 से 6 प्रतिशत तक राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। हमारा पशुधन हमें 35 हजार मेगावाट के बराबर शक्ति प्रदान करता है। देश में कुल विद्युत उत्पादन के अनुपात में देखा जाए तो 50 प्रतिशत के बराबर ऊर्जा पशुधन भी पैदा कर देता है। करोड़ों गैलन गोमूत्र जो यों ही व्यर्थ चला आता है, उत्तम कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

महाराज दिलीप की गोभक्ति प्रसिद्ध है वही करुणावतार भगवान बुद्ध भी गाय की "गाँवों ना परमा मिता" कहकर प्रशंसा करते नहीं अधाते। गाय के दूध की ही खीर खिलाकर सुजाता ने भगवान बुद्ध की जान बचाई थी। वास्तव में गाय के दूध में भैंस की अपेक्षा दस गुना अधिक कैरोटीन बनाने की क्षमता होती है। यह पदार्थ शरीर में विटामिन 'ए' पैदा करता है और सर्वरोगनाशक होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक गोकर्णानिधि में लिखा कि एक गाय अपने जीवनकाल में 5,10,400

मनुष्यों को एक समय का भोजन जुटाती है जबकि उसके मांस से मात्र 80 मनुष्य एक बार अपना पेट भर सकते हैं।

गाय के इसी गुण के कारण मध्यकाल में हिंदुओं पर हुए धार्मिक जुल्मों से बचने में गाय ने बहुत मदद की। जब मुसलमान सुल्तानों और बादशाहों की सेनाएं निशस्त्र हिंदू गाँवों पर लोगों की मुसलमान बनाने के लिए आक्रमण करती थीं तो लोग अपना घर-बार गाँव छोड़कर अपनी गायों के साथ जंगलों में शरण ले लेते थे या पहाड़ों पर भाग जाते थे। प्रवास के इस काल में गऊ ही उनका सहारा होती थी। वयस्क तो यदि कन्दमूल या फल खा भी लेते थे किन्तु शिशुओं और बच्चों को तो मात्र गो दुग्ध का हो सहारा होता था। क्योंकि गाय के कारण हिंदू संघर्ष करने में सफल रहते थे। इसीलिए मुस्लिम सेनाएँ बड़े स्तर पर गोवध करती थीं जिससे हिंदुओं को उनका सहारा न मिले।

दूध के अलावा भी गाय से प्राप्त अन्य उत्पाद भी बहुत काम के होते हैं। रूसी वैज्ञानिक श्री शिरोविच के अनुसार गाय के गोबर से लिये-पुटे घर विकिरण में अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं। गाय के घी द्वारा हवन करने से वातावरण स्वच्छ और सुगंधित हो जाता है। कुछ नवीन शोध के अनुसार गोमूत्र व गोबर में क्षय रोग के कीटाणु मारने की अद्भुत क्षमता पाई गई है।

गोवंश भारतीय कृषि ही नहीं समस्त जीवन का आधार रहा है। जीवन का वह प्रतिरूप जिसे आज हम स्वदेशी कहते हैं गोवंश पर ही आधारित रहा है। वस्तुतः गोवंश रक्षण और स्वदेशी कृषि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे की गति नहीं। यदि इनका हजारों वर्षों से चला आ रहा सामंजस्य पुनः बैठा दिया जाए तो भारत के लिए परमवैभव का लक्ष्य संधान करना और अधिक संभव और आसान हो जाएगा। □□

खुशहाली मुफ्तखोरी में नहीं, स्वदेशी, स्वावलंबन से प्राप्त आत्मनिर्भरता में

— स्वदेशी संवाद



देश में गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। फिर भारत में ऐसी कोई पार्टी नहीं है, जिसने चुनावों के दौरान 'मुफ्त रेवड़ियां' बांटने की सियासत न की हो। गत कुछ दशकों में भारत में लोकप्रियता पाने की दृष्टि से केंद्र सरकार तथा अनेक राज्य सरकारों ने मुफ्त की संस्कृति को आत्मसात् कर लिया है। निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त में गेहूं या चावल देना, गरीब ग्रामीणों को मुफ्त आवास देना, एक सीमा तक मुफ्त बिजली या पानी देना अथवा मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराने की संस्कृति देश के अंदर विकसित हुई है। इस संस्कृति को सभी राजनीतिक दलों ने अपना लिया है। इन दलों को लगता है कि विधानसभा तथा लोकसभा के चुनाव में उनकी सफलता इसी पर निर्भर करती है कि वे

कितनी वस्तुओं तथा सेवाओं को मुफ्त में बांट सकते हैं। सेवाओं, वस्तुओं के निशुल्क वितरण के फलस्वरूप केंद्र सरकार तथा संबद्ध राज्य सरकारों को भले ही लोकप्रियता प्राप्त हो जाए, पर उन्हें वित्तीय भार जिस रूप में वहन करना पड़ता है, उसकी पूर्ति दीर्घकाल तक भी नहीं हो पाती। वास्तविकता यह भी है कि राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों पर कर्ज का भार काफी होने पर भी वे राजनीतिक दबाव के कारण इस तरह की योजनाओं का सहारा ले रहे हैं।

वर्तमान में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त की ऐसी ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जिसका पूरा होना पहले से ही संदेहास्पद और

हास्यास्पद तो है ही, कामकाजी जनता को अकर्मण्य बनाने का आह्वान जैसा भी है।

बिहार विधानसभा चुनाव के महासागर में दोनों प्रमुख गठबंधनों एनडीए और इंडिया महागठबंधन ने अपने-अपने घोषणा पत्रों के जरिए जनता को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। महागठबंधन ने सरकारी नौकरी की गारंटी और कर्मचारियों के अस्थाई करने को केंद्र में रखकर तेजस्वी प्रण प्रस्तुत किया है, तो सट्टा रोड एनडीए ने पंचामृत गारंटी के तहत गरीबों को मुफ्त राशन 125 यूनिट मुफ्त बिजली, पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, 50 लाख नए मकान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के साथ-साथ एक करोड़ सरकारी नौकरी, एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी, आतिश पिछड़ा वर्ग को नगद 10 लाख रुपए देने, के.जी. से पी.जी. तक मुफ्त शिक्षा के साथ-साथ बड़े बजट से लैस कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि शुरू करने की घोषणा की है। दोनों ही गठबंधनों के घोषणा पत्र में वोट जुगाड़ की राजनीति सिर चढ़कर बोल रही है। सरकारी खजाने से मुफ्त की रेवड़ी बांटने में कोई किसी से कम नहीं है।

यह ठीक है कि अर्थव्यवस्था, राजकोषीय घाटा, जीडीपी और कर-संग्रह बेहद महत्वपूर्ण कारक हैं, लेकिन उनके मद्देनजर कोई भी सरकार जनता को गरीबी और भुखमरी की तरफ

नहीं धकेल सकती। नरेन्द्र मोदी सरकार कोरोना काल के दौरान मार्च, 2020 से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज लगातार बांट रही है। देश में खाद्य सुरक्षा का कानून है। फिर भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है। इस योजना पर केंद्र सरकार ने भारी भरकम रकम खर्च किए हैं। आयुष्मान भारत, उज्ज्वला गैस योजना, पक्के घर, नल में जल, शौचालय, किसान सम्मान राशि आदि योजनाएं लगभग निशुल्क हैं। कहने वाले इन्हें भी 'मुफ्त रेवड़ी' की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन उन्हें 'रेवड़ियां' नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे राष्ट्रीय स्तर पर, हर राज्य और हर पात्र नागरिक को, मुहैया कराई जा रही हैं। देश में 6-14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा भी मुफ्त है। हालांकि शीर्ष अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को सलाह दी थी कि 'मुफ्त अनाज' वाली योजना जारी न रखी जाए, क्योंकि उससे हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था असंतुलित भी हो सकती है, लेकिन कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने योजना को जारी रखने का फैसला किया। मकसद था कि इस दौर में देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोना चाहिए।

साफ है, यदि आम नागरिक की जिंदगी, आजीविका, अस्तित्व से जुड़ी कोई परियोजना है, और उसे सरकार निशुल्क ही मुहैया करा रही है, तो उसे 'रेवड़ी' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। भारत एक सामाजिक कल्याण की सोच वाला देश है। लोकतंत्र है, जनता के प्रति सरकार के दायित्व हैं। दरअसल, 'मुफ्त रेवड़ियों' में निशुल्क बिजली-पानी, इलाज, टीवी, साइकिल, लैपटॉप, स्मार्ट फोन, बाइक, साड़ी, मंगल सूत्र, वाशिंग मशीन, प्रेशर कुकर, मुफ्त परिवहन आदि

भारत की जनता को भी समझना होगा कि खुशहाली मुफ्तखोरी में नहीं, आत्मनिर्भर बनने में है। और यह भी तय है कि भारत जैसे देश में खुशहाली स्वदेशी और स्वावलंबन से ही आएगी।

को गिना जा सकता है, जो विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव के मौके पर परोसते हैं, जिसके कारण राज्यों की वित्तीय स्थिति दयनीय होती जा रही है। इनमें असम, बिहार, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, प. बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य प्रमुख हैं। इन राज्यों ने ऋण का भार अधिक होने पर भी लोकप्रिय बनने के लिए अरबों रुपये मुफ्त योजनाओं पर खर्च किए हैं। सवाल है कि ऐसी मुफ्तखोरी से जन-कल्याण कैसे होगा? राज्य ही 'दिवालिया' होने के कगार पर आ जाएंगे। सर्वोच्च अदालत ने भी 'रेवड़ियों' की सियासत पर अपनी चिंता और सरोकार जताए हैं, लेकिन फिलहाल दखल देने से इंकार कर दिया है। 'रेवड़ियों' की संस्कृति ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्यों में दिखी है। लेकिन अब उत्तर भारत के चुनावों में भी इसकी झलक दिखाई देने लगी है।

दरअसल, फ्री की रेवड़ियां, जन कल्याणकारी योजनाओं और लोक लुभावन नीतियों के बीच एक पतली-सी लकीर है। दूसरी तरफ पारदर्शिता या जवाबदेही की कमी, जन-केंद्रित नीतियों के अभाव, सामुदायिक भागीदारी का न होना और ईमानदारी से समीक्षा या

निगरानी न किए जाने के कारण कल्याणकारी योजनाएं देश में कारगर ढंग से लागू नहीं हो पा रही हैं। जिस तरह से योजनाएं बनाई जाती हैं, उनके पीछे सरकार का इरादा क्या है, और इन्हें लागू करने में वह कितनी गंभीर है, इसकी पड़ताल जरूर होनी चाहिए। अधिकतर योजनाएं चुनाव के दौरान लोगों को खुश करने के लिए घोषित की जाती हैं, लेकिन उनके लिए वित्तीय आवंटन निहायत नाकाफी रहता है, जिससे योजना सफल होने से पहले ही दम तोड़ देती है। चाहे केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकारें, जनकल्याण की योजनाओं के लिए साधन आवंटित करते समय इस बात पर फोकस जरूर करना चाहिए कि संबद्ध जनसमूह को मदद की जरूरत है भी कि नहीं। यह भी देखना अपरिहार्य है कि कम से कम कितनी राशि उपयुक्त रहेगी। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें आज पूर्ति आधारित नीति पर चल रही हैं। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि की अनुपालना में प्रत्येक किसान परिवार को छह हजार रुपये किस प्रयोजन से दिए जा रहे हैं तथा किसान इसका किस प्रकार से उपयोग कर रहा है, देश को इसकी जानकारी नहीं है। प्रति वर्ष करोड़ों रुपये व्यय करने के बाद भी सीमांत और लघु कृषकों की आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ, यह चिंता की बात है।

देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के मतानुसार मुफ्त में सामान, सेवा या मुद्रा देना एक प्रकार का वायरस है। राजनीतिक दलों को इस बात की भी परवाह नहीं है कि इससे बैंकिंग व्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित होगी। भारत की जनता को भी समझना होगा कि खुशहाली मुफ्तखोरी में नहीं, आत्मनिर्भर बनने में है। और यह भी तय है कि भारत जैसे देश में खुशहाली स्वदेशी और स्वावलंबन से ही आएगी। □□

स्वदेशी से ही निकलेगा समाधान

— अनूप पाण्डेय



नई आर्थिक नीति, नई विश्व अर्थव्यवस्था, आर्थिक उदारीकरण बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खुला प्रवेश, मुक्त व्यापार ये सब एक ऐसे राक्षस के विभिन्न नाम हैं, जो कई रूपों में भारत जैसे विकासशील देशों पर अपने खूनी पंजे फैलाए हुए हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद हम उपनिवेश के एक दलदल से निकलने में कामयाब हो पाए थे कि सिर्फ पचास के अंतराल पर 90 के दशक से ही एक दूसरे दलदल में फँसते चले गए। करीब दो सौ वर्षों की गुलामी की जंजीर को काटने के लिए विदेशी वस्तुओं की जाने कितनी होलियाँ जलाई गईं और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। यह 'स्व' की भावना थी कि आजादी के हथियार चरखा से निर्मित खादी आजादी की वर्दी कही गई। लेकिन आजादी मिलते ही भारत की कांग्रेस की अगुवाई वाली लोकतांत्रिक सरकार ने 'ऋण कृत्वा धृतं पिबेत्' का सिद्धांत अपना लिया। इसी का नतीजा है कि आज हम आर्थिक उदारीकरण के भयानक भ्रमजाल में फँस गए हैं।

एक बार वर्धा आश्रम में सूत कातते समय नेहरू ने गांधी जी से कहा था कि अभी जितना सूत कतवा लीजिए किंतु आजादी मिलने के बाद हमारी बड़ी-बड़ी मीलें होंगी। प्रत्युत्तर में गांधी जी ने स्पष्ट कहा था— "सूत कातने का महत्व नहीं समझा गया तो आजादी का सुख बहुत दिन तक नहीं भोग पाओगे।" क्या ऐसा हुआ नहीं है?

पूर्ण आत्मनिर्भर स्वर्ग जैसे गाँवों के मेल से बने भारत की समृद्धि और संसाधन को विदेशियों ने कई बार लूटा। परिणामतः सोने की चिड़िया के रूप में चर्चित यह देश कंगाल हो गया। अंततः बड़ी कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त, 1947 को लाल किले के प्राचीर से तिरंगा लहराया। लेकिन इस देश का कृषि और उद्योग इस लायक नहीं रह गया था कि पेट भरने के लिए अन्न और तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़ा भी दे सके। इस स्थिति से निबटने के लिए स्वदेशी नियोजन के बदले विदेशी सहयोग की नीति अपनाई गई। उदाहरणार्थ, ग्रामीण भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। प्रथम योजना में सामुदायिक विकास परियोजना का प्रारूप अमरीका में तैयार किया गया और इसे कार्यान्वित करने के लिए उन्हीं ताकतों से धन और तकनीकी सहयोगी भी लिया गया। दरअसल यहीं से हमारी विकास की योजनाएँ विदेशी गोद में पलने लगीं। देश में सांख्यिकी विकास अवश्य हुआ, किंतु उन्हीं ताकतों द्वारा नियंत्रित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे—विश्व बैंक, मुद्राकोष के जाल में हम बुरी तरह फँस गए और विदेशी निर्भरता हमारी मजबूरी बन गई।

औपनिवेशिक काल के अंत तक अर्थात् आजादी के समय व्यापार का भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में रहा, किंतु आजादी के बाद लगातार भुगतान संतुलन

हमारे विपक्ष में हो गया। नतीजन, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई कि उदारीकरण में इसका समाधान ढूँढा जाने लगा। इस नीति को अपनाते समय तत्कालीन वित्तमंत्री मनमोहन सिंह ने मनमोहनी तर्क दिए—(1) देश को विदेशी मुद्रा संकट से बचाना है। (2) देश को विदेशी कर्ज से मुक्त करना है। (3) देश को बेरोजगारी के चंगुल से बचाकर रोजगार का अवसर देना है। (4) महंगाई पर लगाम लगानी है। (5) देश में व्याप्त गरीबी दूर करके आर्थिक विकास की गति को तेज करना है, आदि—आदि। लेकिन अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों, आर्थिक मामलों के अयोगों और यहां तक की नीति आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया मूल्यांकन रपट ने सिद्ध कर दिया है कि उदारीकरण की नीतियों के बारे में किए गए सरकारी दावे गलत हैं। देश विकास के बदले विनाश की ओर अग्रसर है।

विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 के अंत तक भारत का विदेशी कर्ज बढ़कर 747.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। या मार्च 2025 में 736 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 11.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जून 2025 के अंत तक विदेशी कर्ज से जीडीपी अनुपात घटकर 18.9 प्रतिशत हो गया था। उदारीकरण की नीति लागू करने के समय (मार्च 1991) में देश पर कुल विदेशी कर्ज 1 लाख 63

हजार करोड़ रुपए था जो महज तीन चार साल में (मार्च 1995) में दो गुना बढ़कर 3 लाख 72 हजार करोड़ हो गया था। हाल के बरसों का आंकड़ा देखें तो कोरोना महामारी के पहले वर्ष 2017 में 471 अरब डॉलर, वर्ष 2018 में 529.8 अरब डॉलर, वर्ष 2019 में 543 अरब डॉलर, वर्ष 2020 में 558.5 अरब डॉलर तथा वर्ष 2021 में 570 अरब डॉलर रहा है। क्या यह तथ्य उदारीकरण की असलियत को खोलने में सक्षम नहीं है? क्या यह इस बात का संकेत नहीं है कि एक बार पुनः हमें गुलाम बनाने का प्रयास जारी है?

यह 'मल्टीनेशनल' हमारे लिए एण्टीनेशनल ही दिखने लगी है। पूँजी और तकनीक लाने तथा निर्यात बढ़ाने के नाम पर आई ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां इंस्ट इंडिया कंपनी से कम खतरनाक नहीं है। इनकी पूँजी का नब्बे प्रतिशत से ज्यादा इसी देश में जुटाया गया है। तकनीकी लाने के नाम पर स्थिति शून्य पर है। साबुन, तेल, क्रीम, पेस्ट, ब्लेड, पापड एवं खाद्य पदार्थों में इनकी तकनीक का भ्रमजाल समझा जा सकता है। कृषि प्रधान देशों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नीतियों का खुलासा अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से जारी रिपोर्ट में भी है। इसमें यह दर्शाया गया है कि उदारीकरण की नीतियों के फलस्वरूप कुछ देशों के छोटे-छोटे किसानों के मदद कार्यों में लगातार कटौती की गई, जिससे वहाँ के किसानों की स्थिति सोचनीय हो गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लॉबी संतुलनकर्ताओं को सलाह भी दे रही है और सरकार से यह मांग कर रही है कि 10 हेक्टेयर से कम जोते वाले किसानों को मिल रही सरकारी सुविधाएं बंद की जाएं और बड़े फार्मों को यह सुविधा दिया जाए। क्या इससे भारत के गरीब किसानों पर किसी संभावित खतरे की कल्पना नहीं की जा सकती?

आज स्वदेशी को जीवन के हर क्षेत्र में अंगीकार करने की जरूरत है। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की आर्थिक आजादी को लीलने पर आमादा है।

मौजूदा स्थितियों में उदारीकरण के चलते गैट समझौते के सब्सिडी संबंधी प्रावधानों के तहत जनहित में दी जा रही सब्सिडी में कटौती लगातार बढ़ती जा रही है। यह प्रावधान भारत की जनता के लिए कितना लाभकारी होगा? कृषि, गरीबी, जन स्वास्थ्य, जन सेवाएं एवं साक्षरता, शिक्षा में मिल रही सब्सिडी में कटौती करने के बाद भारत के विकास की गति क्या ठप होने की हालत में नहीं आ जाएगी?

रेल, डाक, बैंक व शिक्षा में निजीकरण चर्चा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह बयान कि विश्वविद्यालयों को अपने स्रोत की खोज करनी चाहिए, किस बात का संकेत है? सबों की चर्चा संभव नहीं है किंतु शिक्षा का निजीकरण विदेशियों के हाथ में चला गया तो हमारे भावी कर्णधारों को यह अवश्य बताया जाएगा कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है। भगत, सुभाष चन्द्रशेखर आतंकवादी और देशद्रोही थे। फिर यह बतलाया जाएगा कि पश्चिमी सभ्यता-संस्कृति महान है: तो क्या यह सब हमारे देश के इतिहास, भूगोल को बिगाड़ने के साथ संस्कृति को नष्ट करने की यह योजना नहीं है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहे भारत महान हैं' के नारे को बेदम नहीं कर देगी क्या?

ऐसी स्थिति में उपाय एक ही दिखता है कि स्वराज्य और स्वावलंबन

को बचाने के लिए स्वदेशी अभियान को और अधिक गति दिया जाए। वास्तव में स्वदेशी अभियान किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए भागीरथ प्रयास है जिसका लाभ मिलना सुनिश्चित है। यूरोप और अमरीका के देशों में यह प्रयोग सफल भी हो रहा है। भारत की आजादी में भी स्वदेशी के प्रतीक खादी ने अपनी सफलता दिखा ही दी है। अगर खादी, स्वयं की मेहनत, पूँजी व तकनीक अर्थात् स्वदेशी को पूर्णतः नहीं अपनाया गया तो वह दिन दूर नहीं, जब हम पुनः एक बार अंग्रेजों की गुलामी से भी बदतर जीवन जीने को विवश हो जाएंगे। मैक्सिको इसका ताजा उदाहरण है।

आज स्वदेशी को जीवन के हर क्षेत्र में अंगीकार करने की जरूरत है। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की आर्थिक आजादी को लीलने पर आमादा है। स्वदेशी जागरण मंच बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कुछ सिद्ध इरादों को भांपते हुए प्रारंभ से ही उनकी नीतियों के विरुद्धन सिर्फ सरकार को आगाह करता रहा है बल्कि समय-समय पर बड़े-बड़े धरना प्रदर्शन आयोजित कर भारत के हित में आवाज उठाता रहा है। वर्तमान दौर में जबकि सरकार भी आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी का समर्थन कर रही है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए स्वदेशी के महत्व पर खासा जोर दे रही है। स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबी भारत अभियान के तहत देशभर में यत्र तत्र सर्वत्र बैठक सेमिनार रैली जुलूस आदि के जरिए लोगों को जोड़ने, उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने तथा नए-नए नवाचार के लिए भी रास्ता तैयार कर रहा है। मंच ने स्वदेशी जागरण का ऐसा वातावरण बनाने का संकल्प लिया है जिससे कि स्वदेशी की रक्षा की संभावना बलवती होने लगी है। यह शुभ संकेत है। □□

“वैश्वीकरण का संकट और स्वदेशी का उदय” विषय पर गोलमेज चर्चा विस्तृत हो गया है स्वदेशी का दायरा: श्री कश्मीरी लाल

स्वदेशी केवल एक आर्थिक नीति नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक सांस्कृतिक, तकनीकी और रणनीतिक दृष्टि भी है। 1905 में औपनिवेशिक शोषण से लड़ने से लेकर विश्व व्यापार संगठन के नियमों को चुनौती देने और आज के वैश्विक डिजिटल प्रभुत्व तक, स्वदेशी की भावना महत्वपूर्ण बनी हुई है। स्वदेशी भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को स्थापित करती है।

स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) के अखिल भारतीय संगठक कश्मीरी लाल ने “वैश्वीकरण का संकट और स्वदेशी का उदय” विषय पर एक गोलमेज चर्चा में बोलते हुए कहा कि “स्वदेशी का दायरा, दृष्टि और अर्थ बहुत विस्तृत हो गया है”। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन (आईपीएफ) द्वारा किया गया था और इसका संचालन आईपीएफ के निदेशक डॉ. कुलदीप रत्नू (स्वदेशी पत्रिका के पूर्व संपादक) ने किया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के कई प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया, जिन्होंने घटते वैश्वीकरण और आत्मनिर्भरता पर नए सिरे से जोर दिए जाने के मद्देनजर स्वदेशी आंदोलन के ऐतिहासिक विकास, वर्तमान महत्व और भविष्य की दिशा पर चर्चा की।

यह चर्चा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई थी। इस संबंध में, कश्मीरी लाल ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका की व्यापार नीतियों में अचानक आए बदलाव को देखते हुए सभी देशों के लिए आत्मनिर्भरता के मुद्दे पर विचार-विमर्श करना ज़रूरी हो गया है। उनके अनुसार, स्वदेशी आज भी शोषण का विरोध करने और स्वतंत्रता की स्थापना की उसी स्थायी भावना में निहित है, लेकिन अब इसका दायरा साइबर सुरक्षा, स्वदेशी हथियार, डेटा संप्रभुता और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे व्यापक क्षेत्रों तक विस्तृत हो गया है।

स्वदेशी के विकसित होते दायरे पर विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जहाँ गांधीजी के काल में स्वदेशी का तात्पर्य केवल वस्त्रों से था, वहीं आज यह बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), माइक्रोचिप्स, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक विस्तृत हो गया है—जिसका प्रतीक चंद्रयान जैसी उपलब्धियाँ हैं। “आज स्वदेशी के बारे में हमारी समझ काफी व्यापक हो गई है। गांधीजी के समय में हम वस्त्रों को स्वदेशी होने पर जोर देते थे, और अब हम चंद्रयान के स्तर तक पहुँच गए हैं। पहले हम आलू के चिप्स जैसे स्वदेशी सनैक्स बनाने की बात करते थे; अब हम स्वदेशी माइक्रोचिप्स बनाने की बात करते हैं।”

उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि युद्ध के तरीके

कैसे विकसित हुए हैं, जिससे स्वदेशी आईटी, रक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म का महत्व लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, “पहले हम सूचनाएँ जुटाने के लिए जासूसों पर निर्भर थे; अब हमारे पास तकनीक है। पहले हमें युद्ध लड़ने के लिए सीमा पार करनी पड़ती थी; आज हम अपने घर बैठे ही उन सीमाओं के पार ड्रोन भेज सकते हैं। अब हम बिना सीमा पार किए ही अपने दुश्मनों को परास्त कर सकते हैं। इसलिए स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों के विकास के साथ स्वदेशी का महत्व और भी बढ़ गया है।”

श्री कश्मीरी लाल ने देश के आत्मनिर्भर भविष्य को आकार देने में भारत के आईटी उद्योग के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने भारत के लिए अपनी स्वदेशी आईटी प्रणालियाँ और प्लेटफॉर्म विकसित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि इनके बिना, देश भविष्य की लड़ाइयों के लिए तैयार नहीं होगा, जो डिजिटल क्षेत्र में तेजी से लड़ी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं में अपनी तकनीकी प्रतिभा और नवाचार के माध्यम से तेल-समृद्ध देशों की आय के बराबर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने की क्षमता है।

अपने उद्घाटन भाषण में, डॉ. रत्नू ने आर्थिक रणनीतियों में वैश्विक बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया भर के देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा और घरेलू रोज़गार की रक्षा के लिए तेजी से अंतर्मुखी हो रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वदेशी, जो कभी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र में था, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय नीति के एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में फिर से उभरा है।

स्वदेशी पत्रिका के पूर्व संपादक ने याद दिलाया कि स्वदेशी का विचार 19वीं शताब्दी में तब पनपा, जब दादाभाई नौरोजी ने एक मौलिक रचना लिखी जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के ब्रिटिश शोषण का विस्तृत विवरण दिया गया था और आर्थिक महत्व के कई मुद्दे उठाए गए थे। उन्होंने बताया कि औपनिवेशिक शासन की उनकी आलोचना ने इस बात पर एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी कि क्या विदेशी शक्तियों को भारत के संसाधनों का दोहन जारी रखने की खुली छूट दी जानी चाहिए।

नौरोजी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए, लोकमान्य तिलक और अरबिंदो घोष जैसे नेताओं ने स्वदेशी को एक आर्थिक दर्शन और एक राष्ट्रवादी आदर्श, दोनों के रूप में आगे बढ़ाया। डॉ. रत्नू ने कहा, “स्व की भावना स्वदेशी में विकसित हुई, जो आगे चलकर राष्ट्रवाद में परिवर्तित हो गई। इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक बड़ी प्रेरणा प्रदान की।” उन्होंने आगे कहा कि “स्व” की अवधारणा भारतीय संस्कृति में निहित है और एक व्यापक एवं गहन सभ्यतागत सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है।

उन्होंने याद दिलाया कि महात्मा गांधी ने चरखे को हथियार बनाकर और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान करके इसे एक नई दिशा दी। इसके साथ ही, ज्यादा लोगों ने स्वदेशी कपड़े पहनना शुरू कर दिया और भारत की अपनी आर्थिक नीतियाँ बनाने की ज़रूरत को समझने लगे। आज़ादी के बाद, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और आयात प्रतिस्थापन में स्वदेशी की अभिव्यक्ति हुई। उन्होंने वैश्विक आर्थिक नियंत्रण के साधन के रूप में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (गैट) और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टीओ) के उदय का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक शक्तियों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसके माध्यम से वे पेटेंट और निवेश के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना चाहती हैं। इसके जवाब में, स्वदेशी जागरण मंच (स्वजाम) ने भारत को पश्चिमी दबावों के आगे झुकने से रोकने और स्वदेशी आंदोलन की निरंतर प्रासंगिकता और आवश्यकता के बारे में भारतीयों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया।

आज, जब दुनिया वैश्वीकरण के रुझानों में उलटफेर देख रही है, तब भारत का स्वदेशी का पुनरुत्थान समयानुकूल और रणनीतिक दोनों है। उन्होंने कहा, “आज, हम विश्व स्तर पर चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हैं, लेकिन एक बार फिर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जिन ताकतों ने अपने निहित स्वार्थों के लिए वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया था, उसने अचानक 180 डिग्री का मोड़ ले लिया है और अब राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद की वकालत कर रही है। इसने अपनी अर्थव्यवस्था और रोज़गार की रक्षा के लिए उच्च शुल्क लगाना शुरू कर दिया है, जिससे वैश्विक आर्थिक व्यवस्था अस्थिर हो रही है।”

इसके बाद हुई चर्चा में, डॉ. रत्नू ने पूछा कि क्या स्वदेशी पर वर्तमान जोर राष्ट्रपति ट्रम्प के टैरिफ और वैश्विक संरक्षणवाद की अचानक प्रतिक्रिया है या किसी सुनियोजित दृष्टिकोण का हिस्सा है। श्री कश्मीरी लाल ने उत्तर दिया कि यह रणनीतिक है, प्रतिक्रियात्मक नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपने व्यापक शासन अनुभव का लाभ

उठाते हुए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसी पहलों के माध्यम से लंबे समय से स्वदेशी के पक्ष में हैं।

उन्होंने याद दिलाया कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब अमेरिका ने यह घोषणा करके अपनी सनक दिखाई थी कि उन्हें अपने देश में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, “इसलिए 2014 में सत्ता में आने से पहले ही, वे अमेरिका के तौर-तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ थे। 2014 में सत्ता में आते ही, प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में भारत के मूल्यों के बारे में जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया।”

श्री कश्मीरी लाल ने बताया कि 7 अगस्त 2015 से स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1905 में इसी दिन हुई थी। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री के प्रयासों के कारण अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे भारत ने दो वैक्सीन सफलतापूर्वक निर्मित कीं, जबकि पश्चिमी देशों ने उन्हें उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया था, जिससे देश की आत्मनिर्भरता की क्षमता का प्रदर्शन हुआ।

प्रधानमंत्री के मन की बात संबोधनों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी बार-बार दोहराए जाने वाले विषय रहे हैं। ‘अब समय आ गया है कि ‘मेक इन इंडिया’ से आगे बढ़कर ‘मेड बाय इंडिया’ और ‘मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियंस’ की वकालत की जाए।’ इस दौरान स्वदेशी शोध संस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री अनिल शर्मा ने रक्षा निर्माण में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला।

चर्चा में, डॉ. रत्नू ने प्रश्न उठाया कि क्या स्वदेशी के लिए वर्तमान आह्वान उसी भावना से प्रेरित हैं जो उस समय थी जब यह आंदोलन पहली बार ब्रिटिश शोषण के खिलाफ और बाद में विश्व व्यापार संगठन द्वारा लगाए गए नियमों के खिलाफ शुरू किया गया था।

श्री कश्मीरी लाल ने जवाब दिया कि बंगाल में 1905 के स्वदेशी आंदोलन को वर्तमान चक्र का पहला कदम माना जा सकता है। उन्होंने टिप्पणी की, “स्वदेशी की भावना वही है। यह शोषण और गुलामी की मानसिकता के खिलाफ है। 1905 में, जब बंगाल पर विभाजन थोपा गया था, लाल, बाल और पाल के नेतृत्व में हुई क्रांति दुनिया की सबसे महान क्रांतियों में से एक थी, क्योंकि यह एक ऐसी आधिपत्य वाली शक्ति के खिलाफ खड़ी हुई थी जिसके बारे में कहा जाता था कि सूरज कभी अस्त नहीं होता।”

उन्होंने कहा कि आज का माहौल भारत के लिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने और स्वदेशी ताकत में निहित वैश्विक

शक्ति के रूप में अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए अनुकूल है। इस बार सरकार और जनता मिलकर स्वदेशी का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए इस आंदोलन की सफलता निश्चित है।”

प्रतिभागियों ने भारतीय स्टार्टअप्स में विदेशी निवेश और गूगल, फेसबुक और अमेज़न जैसे वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभुत्व पर चिंता जताई। डॉ. रत्नू ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया: आर्थिक संप्रभुता पर चर्चा करते समय, क्या स्वदेशी की परिभाषा केवल बाज़ार में बिकने वाली चीज़ों तक ही सीमित होनी चाहिए, या इसका दायरा व्यापक आयामों तक बढ़ाया जाना चाहिए?

श्री कश्मीरी लाल ने कहा कि किसी व्यवसाय को स्वदेशी माने जाने के लिए तीन आवश्यक शर्तें हैं: 1. मालिक भारतीय होना चाहिए। 2. व्यवसाय में प्रमुख शेयरधारक भारतीय होने चाहिए। 3. रॉयल्टी और लाभ भारत के भीतर ही रहने चाहिए। उन्होंने यह भी आगाह किया कि किसी को मार्केटिंग के बहकावे में नहीं आना चाहिए, इसके लिए उन्होंने कोलगेट नामक एक विदेशी कंपनी का उदाहरण दिया, जो वेदशक्ति जैसे भारतीय उत्पादों के नाम से टूथपेस्ट बेचती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भाषा, पहनावा, औषधियाँ और जीवनशैली, सभी में स्वदेशी की भावना झलकनी चाहिए और हमारे त्यौहारों को भी उसी भावना के साथ मनाना उतना ही ज़रूरी है।

डॉ. के.बी. हेडगेवार के शब्दों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि “हमारी टोपी स्वदेशी होनी चाहिए, लेकिन हमारा मन भी स्वदेशी होना चाहिए।”

श्री कश्मीरी लाल ने श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा श्री डेविड मैककॉर्ड राइट को उद्धृत करते हुए याद दिलाया कि उन्होंने कहा था कि “आर्थिक विकास को गति देने वाले मूलभूत कारक गैर-आर्थिक और गैर-भौतिकवादी प्रकृति के हैं।”

इस प्रश्न पर कि क्या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जिनके पुर्जे आयात किए जाते हैं लेकिन अंतिम उत्पाद भारत में ही बनाए जाते हैं, को स्वदेशी वस्तु माना जाना चाहिए, श्री कश्मीरी लाल ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी के समय में भी यही प्रश्न उठा था। उन्होंने कहा था कि “हम अपनी पसंद से देसी हैं” और इसलिए हमें अपने इलाके के सबसे नज़दीक उत्पादित वस्तुओं को खरीदने का सचेत प्रयास करना चाहिए, जो वोकल फॉर लोकल अभियान का सार भी है।

उन्होंने कहा कि यदि कुछ उत्पाद स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं, तो बड़े भारतीय ब्रांडों की ओर रुख करना चाहिए, लेकिन यदि कुछ भारत में पूरी तरह से अनुपलब्ध हैं, तो विदेशी सामान खरीदना अपरिहार्य हो जाता है। हालाँकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लक्ष्य इसे आदत बनाना

नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी आवश्यक वस्तुओं का घरेलू स्तर पर उत्पादन करने का प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने एक छात्र और डॉ. के.बी. हेडगेवार के बीच हुई बातचीत का भी ज़िक्र किया, जिसमें छात्र ने पूछा था कि क्या चश्मा पहनना चाहिए, क्योंकि उस समय भारत में लेंस नहीं बनते थे। डॉ. हेडगेवार ने जवाब दिया कि अच्छी दृष्टि ज़रूरी है, इसलिए चश्मा पहनना ज़रूरी है। हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि फैशनेबल रंगीन चश्मों के आयात से बचा जा सकता है, जो ज़रूरी नहीं थे।

श्री कश्मीरी लाल ने आगे कहा कि यदि भारत तकनीक का आयात कर रहा है, तो उसे चीन और जापान के उदाहरणों का अनुसरण करते हुए मूल्यवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को सबसे पहले संपूर्ण एफएमसीजी क्षेत्र को स्वदेशी बनाने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उन्नत तकनीक की आवश्यकता नहीं होती और इसे आसानी से स्थानीयकृत किया जा सकता है।

ई-कॉमर्स दिग्गजों द्वारा छोटे व्यवसायों को कमजोर करने, बड़ी पूंजी वाली कंपनियों द्वारा भारी छूट का लालच देकर आकर्षिक करने, तथा डाटा संप्रभुता के सवाल पर भी बेबाक टिप्पणी की। उन्होंने श्री श्रीधर वेम्बू का हवाला दिया, जिन्होंने ज़ोहो और अराटाई ऐप जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। श्री कश्मीरी लाल ने देश के युवाओं से इस मिशन को आगे बढ़ाने और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया।

अगले कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए, श्री कश्मीरी लाल ने पाँच मुख्य क्षेत्रों पर जोर दिया: 1. रेहड़ी-पटरी वालों और दुकानदारों को प्रोत्साहित करना और उन्हें स्वदेशी आंदोलन के बारे में जागरूक बनाना। 2. स्कूलों में स्वदेशी जागरूकता ले जाना ताकि छोटी उम्र से ही आत्मनिर्भरता का विचार उनमें पैदा हो सके। 3. व्यापक सामुदायिक भागीदारी के लिए सामाजिक समूहों को शामिल करना। 4. संदेश को प्रभावी ढंग से फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना। 5. भविष्य के लिए इसकी निरंतरता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को इस आंदोलन में शामिल करना।

स्वदेशी केवल एक आर्थिक नीति नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक सांस्कृतिक, तकनीकी और रणनीतिक दृष्टि भी है। 1905 में औपनिवेशिक शोषण से लड़ने से लेकर विश्व व्यापार संगठन के नियमों को चुनौती देने और आज के वैश्विक डिजिटल प्रभुत्व तक, स्वदेशी की भावना महत्वपूर्ण बनी हुई है... भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को स्थापित करती है। □□

एकात्म मानव दर्शन का सर्वोदय

भारतीय विचार प्रवाह में सितंबर महीना महत्व का है क्योंकि इस माह में ऐसे दो व्यक्ति ने जन्म लिया जिन्होंने भारतीय विचार को आधुनिक मोड़ दिया। एक थे विनोबा भावे और दूसरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वैसे विनोबाजी दीनदयाल जी से करीब 20 वर्ष से बड़े थे और दीनदयालजी के बाद लगभग 14 वर्ष ज्यादा ज़िंदा रहे। लेकिन दोनों के विचारों ने स्वतंत्र भारत की सभी सामाजिक आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया है। विनोबाजी ने महात्मा गांधी के विचारों को स्पष्ट करते हुए सर्वोदय विचार को रखा और दीनदयालजी ने एकात्म मानव दर्शन को। दोनों ने भौतिकवादी साम्यवाद को नकारा और भारतीय प्राचीन सभ्यता एवं दर्शन को आधार बनाकर अपने विचार रखे। इसलिए यह एक बड़ा योगदान रहा और इस पर समन्वयात्मक चर्चा होनी चाहिए।

विनोबाजी और दीनदयाल जी – व्यक्तित्व और कार्य

विनोबा भावे (1895–1982) का जन्म महाराष्ट्र के एक गाँव में हुआ। वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे और जीवनभर अविवाहित रहकर उन्होंने तपस्वी, सादगीपूर्ण और आध्यात्मिक जीवन जिया। बीस-इक्कीस वर्ष की आयु में उनकी गांधीजी से भेंट हुई और जीवनभर उन्होंने गांधीजी के शिष्य और उत्तराधिकारी के रूप में गांधीजीके विचारों को स्पष्ट किया और प्रचार किया। गांधीवाद को स्पष्ट करते हुए उन्होंने सर्वोदय का विचार दिया। भूदान व ग्रामदान आंदोलनों के माध्यम से सर्वोदय के सिद्धांतों को प्रत्यक्ष उतारनेकी कोशिश भी की। उनके गीता प्रवचन और अन्य वैचारिक साहित्य ने उन्हें नैतिक-आध्यात्मिक नेता के रूप में भी प्रतिष्ठित किया। दूसरी ओर पंडित दीनदयाल उपाध्याय (1916–1968) का जन्म उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ और बचपन में ही अनाथ हो जाने के बावजूद वे गहन चिंतक, संगठनकर्ता और राष्ट्रभक्त बने। वे भी 20–21 वर्ष की आयु में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संपर्क में आए और अविवाहित रहकर अपना जीवन राष्ट्रसेवा को समर्पित किया। संघ की प्रेरणा से ही भारतीय जनसंघ के संगठन को मजबूत किया। संघटन को दिशा देने हेतु ही 1965 में उन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन प्रतिपादित कर राजनीति में भारतीय संस्कृति और नैतिकता को जोड़ा। पत्रकारिता के क्षेत्र में पांचजन्य और राष्ट्रधर्म जैसे पत्रों का संपादन कर इस विचार को प्रसारित किया। जहाँ विनोबा भावे ने समाज और ग्रामीण जीवन में नैतिक जागृति लाने का कार्य किया, वहीं दीनदयाल उपाध्याय ने राजनीति और शासन को भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि से जोड़कर राष्ट्र जीवन को दिशा देने का प्रयास किया। आज विनोबाजी का सर्वोदयवाद लगभग भुलादिया गया है लेकिन भारतीय जनता पक्ष ने एकात्म मानव दर्शन को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है और अमल में लाने की कोशिश में है।



सर्वोदय और एकात्म मानव दर्शन दोनों ही भारतीय चिंतन की ऐसी धरोहरें हैं जो आज भी समाज और राष्ट्र के लिए मार्गदर्शन देने में सक्षम हैं।

— अनिल जवलेकर

क्या है सर्वोदय विचार और एकात्म मानव दर्शन

सर्वोदय विचार महात्मा गांधी के रामराज्य की कल्पना द्वारा प्रतिपादित और बाद में विनोबा भावे द्वारा विकसित एक समग्र सामाजिक दर्शन है, जिसका अर्थ है सबका उदय या सबका कल्याण है। इसमें समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक सुख और सुरक्षा पहुँचाना ही प्रगति की कसौटी मानी जाती है। इसके मूल सिद्धांत हैं – अहिंसा और सत्य पर आधारित जीवन, आर्थिक व सामाजिक समानता, ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता, संपत्ति पर न्यासत्व

(ट्रस्टीशिप), तथा सबको समान अवसर व सम्मान देना। भूदान, ग्रामदान और संपूर्ण क्रांति जैसे आंदोलनों के माध्यम से सर्वोदय को व्यवहार में उतारने का प्रयास किया गया। एकात्म मानव दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी द्वारा प्रतिपादित एक मौलिक जीवनदर्शन है, जिसका उद्देश्य समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए संतुलित दृष्टिकोण देना है। इसमें मनुष्य को केवल आर्थिक प्राणी या राजनीतिक प्राणी मानने के बजाय उसके चारों आयामों — शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, का समन्वय मान्यता प्राप्त है। यह दर्शन व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच संतुलन पर बल देता है और विकास को केवल भौतिक उन्नति तक सीमित न रखकर नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नयन से जोड़ता है। इसका मूल संदेश है कि राष्ट्र एक जीवंत इकाई है, और नीतियों का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुख-सुविधा पहुँचाना होना चाहिए, ताकि व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र — सभी का सामंजस्यपूर्ण विकास हो सके।

सर्वोदय और एकात्म मानव दर्शन—एक ही सिक्के के दो पहलू

सर्वोदय और एकात्म मानव दर्शन दोनों का लक्ष्य सबका कल्याण है, और दोनों की दृष्टि में थोड़ा ही अंतर है। सर्वोदय महात्मा गांधी और विनोबा भावे का विचार है, जो अहिंसा, सत्य, न्यासत्व (ट्रस्टीशिप), भूदान—ग्रामदान और ग्राम स्वराज पर आधारित होकर समाज के हर वर्ग, विशेषकर गरीब और वंचित के उत्थान पर केंद्रित है। दूसरी ओर, एकात्म मानव दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नीति प्रधान विचार है, जो व्यक्ति के चारों आयामों—शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, के संतुलित विकास को आवश्यक मानता है और राष्ट्र को एक जीवंत सांस्कृतिक इकाई मानकर स्वदेशी

अर्थनीति तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर बल देता है। इसमें भी अंत्योदय का विचार सम्मिलित है। सर्वोदय सामाजिक आंदोलन को माध्यम बनाकर सामाजिक—आर्थिक सुधार की दिशा देना चाहता है, जबकि एकात्म मानव दर्शन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के समग्र विकास का वैचारिक दर्शन प्रस्तुत करता है और राजनैतिक तौर पर नीति अपनाने की चेष्टा करता है। आज का 'सबका साथ सबका विकास' दोनों का समन्वय करता दिखता है।

दोनों विचारों की आज की स्थिति

यह सही है कि सर्वोदय और एकात्म मानव दर्शन दोनों ही भारतीय समाज और राजनीति में अलग-अलग रूपों से प्रभाव डाला हैं। विनोबाजी के देहांत के बाद सर्वोदय विचार पर बात कम ही होती है। लेकिन भाजपा तथा संघ परिवार ने दीनदयाल जी के विचार को चर्चा में रखा है। सर्वोदय विचार, जो गांधी जी और विनोबा भावे के भूदान—ग्रामदान, न्यासत्व और ग्राम स्वराज जैसे प्रयोगों पर आधारित था, अब बड़े आंदोलन के रूप में सक्रिय नहीं है लेकिन भारतीय परंपरा और संस्कृति से जुड़ा होने के कारण भारतीय जीवन को आज भी प्रवाहित करता है। आज भी विकास, सामाजिक न्याय, सहकारी आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण, स्वावलंबी ग्राम अर्थव्यवस्था और सेवा—आधारित सामाजिक कार्य में सर्वोदय की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। दूसरी ओर, एकात्म मानव दर्शन, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी ने प्रतिपादित किया, आज भारतीय राजनीति और शासन का प्रमुख वैचारिक आधार बन चुका है। "अंत्योदय"—सबसे अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएँ और अवसर पहुँचाने का सिद्धांत—आज जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन और ग्रामीण आवास योजनाओं में व्यवहार रूप में उतरा

हुआ है। इस दर्शन में व्यक्ति के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन और राष्ट्र को सांस्कृतिक इकाई मानने का विचार भी शामिल है, जो आज की नीतियों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और समग्र विकास के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार, जहाँ सर्वोदय सामाजिक—सांस्कृतिक आंदोलनों और वैकल्पिक विकास मॉडल को दिशा देता रहा है, वहीं एकात्म मानव दर्शन भारत के राजनीतिक—शासन तंत्र को वैचारिक आधार प्रदान कर रहा है।

दोनों का समन्वय आवश्यक

सर्वोदय और एकात्म मानव दर्शन दोनों ही भारतीय चिंतन की ऐसी धरोहरें हैं जो आज भी समाज और राष्ट्र के लिए मार्गदर्शन देने में सक्षम हैं। सर्वोदय हमें अहिंसा, ग्राम स्वराज, न्यासत्व, समान अवसर और सतत विकास की दिशा दिखाता है, जिससे सामाजिक न्याय और पर्यावरण संतुलन सुनिश्चित होता है; वहीं एकात्म मानव दर्शन व्यक्ति के शरीर—मन—बुद्धि—आत्मा के संतुलन और राष्ट्र को जीवंत सांस्कृतिक इकाई मानते हुए "अंत्योदय" अर्थात् अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएँ पहुँचाने की प्रेरणा देता है। यदि इन दोनों विचारों का समन्वय किया जाए तो एक ओर समाज में नैतिकता, सहयोग और आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा और दूसरी ओर राष्ट्रीय नीतियाँ सांस्कृतिक आधार पर सबको समेटने वाली बनेंगी। इस प्रकार, सर्वोदय और एकात्म मानवदर्शन आज भी भारतीय समाज और शासन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन और संतुलित विकास का आधार प्रस्तुत करते हैं। इसलिए सर्वोदय और एकात्म मानव दर्शन बहुत अलग नहीं है। सर्वोदय राजनीत या सत्ता को विकास का जरिया नहीं मानता जब कि एकात्म मानवदर्शन भारतीय राजनीति का हिस्सा बन गया है। लेकिन यह नहीं भुलाया जा सकता कि भारतीय नीति में दोनों उपयोगी है। □□



केंद्रीय कार्यसमिति बैठक भाग्यनगर, हैदराबाद (तेलंगाना) (20-21 सितंबर, 2025)

स्वदेशी जागरण मंच की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक 20 एवं 21 सितंबर 2025 को उस्मानिया विश्वविद्यालय, भाग्यनगर में सम्पन्न हुई। बैठक में स्वदेशी जागरण मंच सहित किसान संघ, विद्या भारती, सहकार भारती, भारतीय जनता पार्टी, सेवा भारती, कनेरी मठ एवं बड़े व्यापारी संगठन कैट के प्रतिनिधियों सहित 65 वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक का आरम्भ मंच के अखिल भारतीय (अ.भा.) संयोजक श्री आर. सुन्दरम, अ.भा. संगठक श्री कश्मीरी लाल, अ.भा. सह-संयोजक प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा, डॉ. अश्वनी महाजन, प्रो. राजकुमार मित्तल, अ.भा. सह-संगठक श्री सतीश कुमार, महिला प्रमुख श्रीमती अर्चना मीना द्वारा भारत माता, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी एवं श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्ज्वलन एवं भारत माता की जयघोष के साथ हुआ।

प्रारम्भ में श्री सतीश कुमार, अ.भा. विचार विभाग प्रमुख डॉ. राजीव कुमार द्वारा मंचासीन अधिकारियों एवं स्वावलम्बी भारत अभियान में सहयोगी संगठनों भारतीय किसान संघ से श्री कुमारस्वामी, सेवा भारती से श्री विनोद बिडला, सहकार भारती से श्री विनय खटावकर, भाजपा से श्री एच. राजा, विद्या भारती से श्री ज्वाला प्रसाद, कैट से श्री बी.एल. भरतिया, कनेरी मठ से श्री रविन्द्र सिंह का परिचय कराया गया।

प्रस्ताविक भाषण में स्वदेशी जागरण मंच के अ.भा. संयोजक श्री आर. सुन्दरम ने पहलगाव की घटना एवं सिंदूर

ऑपरेशन के बाद भारतीय उद्यमियों, निर्यातकों एवं व्यापारियों के लिए उत्पन्न चुनौतिपूर्ण स्थिति को कोरोना काल के समान अवसर बताया, जो केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर चुनौतिपूर्ण है। जिसमें कुछ समय के लिए कठिनाई जरूर होगी लेकिन इसका समाधान भी भारतीय उद्यमी, निर्यातक एवं व्यापारी निकाल कर देश को निरंतर विकास की ओर ले जाने में समर्थ होंगे।

श्री सतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक में आयाम, आंदोलनों एवं अभियानों की वैचारिक चर्चा के बाद क्षेत्रों से आये कार्यकर्ताओं की जानकारी ली। सभी 11 क्षेत्रों का कार्यवृत्त निवेदन हुआ। वृत्त निवेदन में पिछले तीन माहों में स्वावलम्बी भारत अभियान, स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलम्बन अभियान के अंतर्गत किये गये कार्य विस्तार, प्रवासों, रैलियों, पत्रक-वितरण, व्यापारिक संगठनों से सम्पर्क इत्यादि की जानकारी क्षेत्र संयोजकों द्वारा दी गयी।

दक्षिण क्षेत्र का वृत्त निवेदन क्षेत्र समन्वयक श्री सत्यनारायण, दक्षिण मध्य क्षेत्र का क्षेत्र संयोजक डॉ. एस. लिंगामूर्ति, पश्चिम क्षेत्र का क्षेत्र समन्वयक श्री विनय खटावकर, मध्य क्षेत्र का क्षेत्र संयोजक श्री सुधीर दाते, राजस्थान क्षेत्र का क्षेत्र संयोजक श्री सतीश आचार्य, उत्तर क्षेत्र का क्षेत्र समन्वयक श्री राजेश गोयल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र का क्षेत्र संयोजक श्री अमितेश अमित, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र का क्षेत्र संयोजक श्री अनुपम श्रीवास्तव, बिहार झारखंड क्षेत्र का

क्षेत्र संयोजक श्री अमरेन्द्र, पूर्वी क्षेत्र का क्षेत्र संयोजक श्री आशुतोष मुखर्जी, पूर्वोत्तर क्षेत्र का क्षेत्र समन्वयक डॉ. तरनी डेका ने कार्यवृत्त प्रस्तुत किया।

डॉ. राजीव कुमार ने स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलम्बन अभियान की पृष्ठभूमि में पहलगांव की आतंकवाद की घटना तथा फिर भारत सरकार द्वारा जवाब देने से लेकर दिल्ली में देशभर के 500 से अधिक सामाजिक, आर्थिक, किसान, उद्योग संगठनों के समर्थन देने से दिनांक 12 जून 2025 को एन.सी.यू.आई. के सहकारिता भवन दिल्ली में स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलम्बन अभियान की शुरुआत करने तथा देश के सभी 45 प्रांतों में स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबी भारत अभियान के विषय में जानकारी दी।

श्री सतीश कुमार ने स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलम्बन अभियान की गति बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं से चर्चा की, जिसमें अनेक सुझाव आये। सर्वप्रथम सभी की सहमति से तय हुआ कि स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान को अब स्वदेशी स्वावलंबी भारत अभियान के नाम से जाना जायेगा।

प्राप्त सुझावों में प्रमुख रूप से प्रत्येक जिले में स्वदेशी संकल्प यात्राओं का आयोजन, जिलों में मोटरसाइकिल यात्रा, प्रचार कार्यक्रम पर जोर, जगह-जगह स्वदेशी मेलों का आयोजन, अभियान को महापुरुषों धार्मिक कार्यक्रमों से जोड़ना, स्वदेशी उत्पादों को उपयोग में लेने पर लगातार चर्चा करना, जिला स्तर पर व्यापारियों के साथ हर माह बैठक करना, कार्यकर्ताओं का परिवार मौहल्ले के अन्य 5 परिवारों को स्वदेशी परिवार के लिए तैयार करना, हर जिले में स्वदेशी दुकान अथवा स्वदेशी स्टोर खुलवाना आदि।

इसके बाद श्री सतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ अभियान को लेकर पाँच सूत्रों पर चर्चा की—

1. छोटे-बड़े व्यापारियों को अभियान का वाहक बनाना,
2. शैक्षणिक संस्थानों को अभियान से जोड़ना,
3. धार्मिक सन्त समाज, आध्यात्मिक महापुरुषों को अभियान से जोड़ना,
4. सामाजिक संगठनों के प्रमुखों के माध्यम से अभियान को समाज तक ले जाना,
5. प्रचार के माध्यम से अभियान को जन आन्दोलन बनाना।

स्वदेशी शोध संस्थान की सचिव डॉ सरबजीत कौर ने स्वदेशी शोध संस्थान के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शोध संस्थान 2018 से कार्य में आया, जो कृषि, विनिर्माण, सेवा सेक्टर के क्षेत्र में शोध कार्य करेगा। उन्होंने शोध संस्थान के लिस्ट ऑफ चेप्टर में हरियाणा, चण्डीगढ़, चैनई, पंजाब, रिसर्च पेपर, बुक, न्यूजलेटर एवं इन्टरनेशनल कॉन्फ्रेंस एवं क्रियाकलापों के विषय पर चर्चा की।

स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन के चेयरमैन श्री सतीश

चावला ने स्वर्णिम भारत फाउण्डेशन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सेक्शन-8 कम्पनी होने के कारण दानदाता को हाथों-हाथ ऑनलाइन आयकर में छूट की रसीद मिलती है, पहले 28 प्रांतों में और अब 10 अन्य खातें खुलने से कुल 38 प्रांतों में स्वर्णिम भारत फाउण्डेशन के खाते खुल चुके हैं।

श्री हिमांशु जोशी ने पीपीटी की सहायाता से वित्त प्रबंधन, कार्यालय एवं स्वावलम्बी केंद्र की जानकारी के साथ ही 45 प्रांतों में से 30 प्रांतों में पूर्णकालिक कार्यकर्ता होने की जानकारी दी।

श्री बटुकेश्वर झा (प्रांत समन्वयक, बंगाल) ने कोलकाता में आयोजित उद्यमिता संगम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस आयोजन में प्रथम श्रेणी के उद्यमियों को प्रोत्साहन के लिए 950 युवाओं की सहभागिता सहित 480 उद्यमी, विद्यार्थियों एवं अन्य समविचारी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ ही निदेशक आई.आई.टी. खडकपुर भी उपस्थित हुए।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बालकृष्ण भरतिया ने नागपुर में आयोजित स्वदेशी व्यापारी जुटान के संबंध में बताया कि व्यापारी जुटान में 46 संगठनों को निमंत्रण दिया गया, जिसमें 43 संगठन एवं 40 से अधिक रेडी-पटरी वाले छोटे व्यापारी भी उपस्थित हुए। इसमें हॉकरों की समस्या, ई-कॉमर्स के लिए आवश्यक नियमों को कड़ाई से पालन एवं व्यापार क्रेडिट कार्ड की सुविधा आदि विषयों पर व्यापारियों ने अपनी बातें, सुझाव दिए।

भारत में स्वदेशी उत्पादों की खपत बढ़ाने की चर्चा के साथ सयुक्त घोषणा कर अभियान को तहसील, कस्बों तक ले जाने, अभियान को सयुक्त रूप से चलाने के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता लगाने, स्वदेशी कोष निर्माण, ऑन लाईन व्यापार के लिए नियामक बोर्ड गठन पर सहमति बनी।

श्री राधेश्याम चोयल ने डिजिटल माई.एस.बी.ए. वेबसाइट की जॉब, करियर, स्वदेशी स्टॉल्स, समाचार, सहित आगामी योजनाओं के बारे में जिसमें साहित्य, स्वदेशी गीत एवं नारों के साथ ही कार्यकर्ताओं, व्यापारियों, नये उद्यमियों एवं ग्राहकों के साथ जुड़ने के संबंध में जानकारी दी।

डॉ राजकुमार चतुर्वेदी (अ.भा. सम्पर्क प्रमुख) ने प्रजनन दर-युवा जनसंख्या विकास पर देश की वर्तमान स्थिति, भविष्य में देश पर पड़ने वाले प्रभाव, विश्व के संदर्भ में भारत, भारत में बदलती परिवार पद्धति पर पीपीटी के माध्यम से चर्चा की गई। इसके बाद दो पुस्तकों, जिनमें डॉ राजकुमार चतुर्वेदी द्वारा लिखित 'युवा जनसंख्या-समृद्धि का आधार' एवं डॉ सुनिता बर्थवाल जी द्वारा लिखित पुस्तक 'स्वदेशी आत्मशक्ति' का विमोचन हुआ।

श्री विनोद बिडला (सेवा भारती) के अनुसार सेवा भारती में चार आयाम में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलम्बन एवं

सेवा है, जिसमें स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत 1071 सिलाई केंद्र, 222 मेहंदी केंद्र, 5 नर्सरी, 166 कम्प्यूटर सेंटर, 10 प्रतियोगिता प्रशिक्षण केंद्र, 4 गौ उत्पाद केंद्र, 18 कोटेज, 272 हेण्डिकाप्ट, 62 स्वरोजगार सेंटर एवं 33 सर्विस होम केयर सेंटर चल रहे हैं।

श्री कुमार स्वामी (भारतीय किसान संघ) के अनुसार रोजगार आयाम के अंतर्गत 742 एफपीओ, 10 हजार स्कीम में 530 सेंटर, 10 राज्यों में पंजीयन कर फुड प्रोसेज एवं एफपीओ प्रशिक्षण, मार्केटिंग, ऐगजीबिशन, नेशनल लेवल पर आयोजित किये जा रहे हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद (विद्या भारती) के अनुसार 27 विषयों में से स्वदेशी एक विषय है। कौशल विकास के लिए विद्या भारती ने एन.सी.वी.ई.टी. के साथ एम.ओ.यू. किया गया है। देशभर में आयोजित होने वाले मातृशक्ति सम्मेलनों में स्वदेशी एवं उद्यमिता विषय रखा गया।

श्री रविन्द्र सिंह (कनेरी मठ) के अनुसार मठ जैविक खेती सहित 20 से 25 आयाम चला रहा है। जिसमें से पांच आयामों— प्राकृतिक कृषि, चिकित्सा, वेदपाठ, शिक्षा, गौ एवं महिला सशक्तिकरण पर कार्य हो रहा है।

श्री विनय खटावकर (सहकार भारती) के अनुसार सहकार भारती महाविद्यालयों में सहकारिता से उद्यमिता की ओर अभियान के अन्तर्गत भाषण, स्टार्ट अप, उद्यमिता के लिए ऋण—कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से जिसमें कॉर्पोरेटिव पॉलिसी 80 प्रतिशत वहन करती है, आदि गतिविधियों के माध्यम से उद्यमिता एवं स्वावलंबन को बढ़ावा दे रही है।

श्री प्रशांत देशपाण्डे ने उद्यमिता संगम के अंतर्गत एम.एस.एम.ई. के उद्यमियों को प्रोत्साहन के साथ चर्चा के माध्यम से मार्गदर्शन एवं समस्याओं के समाधान पर ध्यान देने पर जोर दिया।

प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा ने वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य एवं भारतीय कृषि विषय पर बताया कि उपजाऊ जमीन एवं पानी के प्रबन्धन से किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में मूल्यवर्धन करने पर जोर दिया जाना चाहिए। खाद्य तेलों के आयात एवं एफडीआई के चलते 50 प्रतिशत लाभांश देश से बाहर जा रहा है। आयात को उत्पादन में बदलना होगा। हाई टेक्नोलोजी, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंसी, सेमीकण्डेक्टर, चीन से व्यापार, विनिर्माण सेक्टर की आवश्यकता, विनिर्माण विकास इण्डस्ट्रीज, मेक इन इण्डिया, पीएलआई, नई इण्डस्ट्रीज पॉलिसी, आदि पर नये स्तर पर जाकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

डॉ. अश्वनी महाजन ने विकास का भारतीय प्रतिमान विषय पर कहा कि जीडीपी को विकास से जोड़ने की भ्रांतियां चल रही हैं। भारत का चार पुरुषार्थों पर विश्वास है,

जिसमें से अर्थ महत्वपूर्ण है लेकिन इसका अभाव एवं प्रभाव दोनों ही खतरनाक है। इसलिए अर्थ का नियोजन—प्रयोजन धर्म के परिवेश में होना चाहिए। पाश्चात्य विकास की अवधारणा में टुकड़ों में विकास के कारण ही बेकारी, भूखमरी, पूंजी असंतुलन एवं स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुई है। एकात्मदर्शन, सम्पूर्ण बहमाण्ड की चिंता एवं सह अस्तित्व की भावना के साथ ही धर्म एवं पर्यावरण के आलोक में ही सबकुछ व्यवस्थित रूप से किया जा सकता है। इसलिए लघु उद्योगों के साथ ही रेडी—पटरी वाले छोटे व्यापारियों के बारे में सोचना एवं कृषि में जीएम, रसायनिक खेती से बचना जरूरी है।

भारत ग्लोबल इण्डस्ट्रीज फोरम के श्री सिद्धार्थ शर्मा ने लघु उद्योग से बड़ी कम्पनियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के प्रयास पर बल दिया। लार्ज भारतीय इण्डस्ट्रीज में 30 सदस्य हैं, अभी इन कम्पनियों को मार्गदर्शन देने के लिए हमें ही प्रयास करने होंगे। यह फोरम ही 'नेशन फर्स्ट' की विचारधारा के कारण ही भारत को 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में लेकर जाने वालों का फोरम होगा, जो विदेशों से भारतीय कम्पनियों को भारत में लाने का प्रयास कर सकता है। इसलिए 31 अगस्त 2025 को भारत मण्डप, दिल्ली में आयोजित सेमिनार में इसी विषय पर फोकस किया गया।

श्री सचिन्द्र बरियार एवं श्री साकेत राठौर के अनुसार भारत के किसी भी प्रांत में स्वदेशी मेलों के आयोजन के लिए संगठन के पास पर्याप्त मात्रा में आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से सक्षम प्रशिक्षित टीम, स्थानीय संरचना, कार्यालय, कार्यकर्ता, कोष के कारण स्वदेशी मेलें लगाना आसान है। स्वदेशी मेले समाज में एक ब्रान्ड है जो समाज का नेतृत्व करने में सक्षम होने के साथ ही जमीनी स्तर के उद्यमियों को लेकर चलने वाले बड़े मॉडल के रूप में विस्तारित किये जा सकते हैं।

श्री एच. राजा (भारतीय जनता पार्टी) ने भाजपा द्वारा 25 सितम्बर से 25 दिसम्बर (3 माह) तक पूरे देश में चलाए जाने वाले स्वदेशी एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान के विषय में जानकारी दी।

अ.भा. संघर्षवाहिनी प्रमुख श्री अन्नदाशंकर पाणिग्रही ने पर्यावरण विषय पर स्वदेशी मेलों में प्लास्टिक के स्थान पर स्टील्स के बर्तनों का उपयोग, सतत विकास की चुनौतियों में पर्यावरण, रोजगार, उर्जा सहित पांच विषय पर चर्चा की। इसके लिए प्रकृति यात्रा कार्यक्रम पूजन, वन—नदी यात्रा, विचार गोष्ठी का आयोजन, भूमि सूपोषण के कार्यक्रम एवं 28 अगस्त अमृता देवी बलिदान दिवस पर कार्यक्रम करने का आह्वान किया।

डॉ प्रतिभा चतुर्वेदी (अ.भा. सह महिला प्रमुख) के अनुसार अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में 45 में से 38

प्रांतों ने 30 एवं 31 अगस्त 2025 को 14 शोध पत्रों का वाचन किया गया।

श्री सतीश कुमार के अनुसार स्वदेशी जागरण मंच 1991 को गेट, डंकल प्रस्ताव, विश्व व्यापार संगठन के खिलाफ एक जन आन्दोलन के रूप में जन्मा है। स्वदेशी आंदोलन भारत को वर्ल्ड इकॉनमी बनाने का बीज है। हमें कुछ मार्केट्स पर भी कब्जा करना पड़ेगा। यह आर्थिक सुधार नहीं, आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशनल का विषय है। सेमीकंडक्टर चिप्स, एयरटूल्स, आई.टी. सेक्टर, हैवी इंजीनियरिंग एवं जैविक खेती सभी में भारत का विकास छिपा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अनेक सोर्सिंग के माध्यम से आर्थिक विषयों की जानकारी करें, जैसे 'अमरीकी टैरिफ रेट' इस विषय को गहनता से पढ़ें तथा इस पर चर्चा करें।

श्री आर. सुन्दरम एवं श्री कश्मीरी लाल ने नवीन दायित्वों की घोषणा की गयी।

नवीन दायित्व

अखिल भारतीय दायित्व

- **प्रो. सोमनाथ सचदेवा** – पूर्व में उत्तर क्षेत्र संयोजक, अब स्वदेशी शोध संस्थान के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे।
- **श्रीमती अमिता पत्की** – पर्यावरण आयाम की राष्ट्रीय सह प्रमुख होगी।
- **श्री के. जगदीश** – दक्षिण मध्य क्षेत्र संगठक के साथ ही स्वदेशी मेला की राष्ट्रीय टोली के सदस्य होंगे।

मध्य क्षेत्र

- **श्री आलोक सिंह** – पूर्व में महाकौशल प्रांत संयोजक थे, अब मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे।
- **श्री कपिल मलैया** – पूर्व में महाकौशल प्रान्त के अभियान समन्वयक थे, अब प्रांत संयोजक के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

उत्तर क्षेत्र

- **श्री राजेश गोयल** – उत्तर क्षेत्र के संयोजक का दायित्व निर्वहन करेंगे।

दक्षिण मध्य क्षेत्र

- **श्री रमेश** – पूर्व में तेलंगाना प्रान्त के अभियान समन्वयक थे, अब दक्षिण मध्य क्षेत्र के समन्वयक होंगे।
- **सीए हरीश बाबू** – तेलंगाना प्रान्त संयोजक के साथ ही दक्षिण मध्य क्षेत्र के सम्पर्क प्रमुख भी होंगे।
- **श्री राचा श्रीनिवास** – तेलंगाना प्रान्त संगठक के साथ ही आन्ध्र प्रदेश के सम्पर्क प्रमुख भी होंगे।
- **श्री इन्द्रसैन रेड्डी** – पूर्व में तेलंगाना प्रान्त अभियान के सह समन्वयक थे, अब प्रान्त समन्वयक होंगे।
- **श्री मन्जुनाथ** – पूर्व में अभियान के क्षेत्र समन्वयक थे, अब क्षेत्र के पर्यावरण प्रमुख एवं क्षेत्र कार्यकारिणी सदस्य होंगे।

पश्चिम क्षेत्र

- **श्री भूषण जी वैद्य** – पश्चिम क्षेत्र के सम्पर्क प्रमुख होंगे। (पूर्व में लघु उद्योग भारती में दायित्व रहा है)
- **श्री ईश्वर सज्जन सिंह** – पश्चिम क्षेत्र के सह-क्षेत्र सम्पर्क प्रमुख होंगे (पूर्व में लघु उद्योग भारती में दायित्व रहा)
- **श्री संभाजी रावुरे (सहकार भारती)** – प्रान्त सह समन्वयक, देवगिरी प्रांत (श्री तुलजेश जी चौधरी, जालना के स्थान पर)
- **श्री शरद भाई ठक्कर** – प्रान्त सह समन्वयक, गुजरात
- **डॉ. सीमा बेन गाला (वापी)** – पूर्व में गुजरात महिला कार्य सह प्रमुख, अब प्रान्त महिला कार्य प्रमुख होगी।
- **श्रीमती नीना बेन भट्ट** – प्रान्त महिला कार्य सह प्रमुख के साथ ही प्रान्त सह समन्वयक (महिला) होगी।

श्री कश्मीरी लाल ने वर्तमान के माहौल के साथ-साथ अपना कार्य, कार्यक्रम, अभियान के लिए लगातार कार्य करते रहने के लिए आह्वान किया। इसके लिए वातावरण की अनुकूलता को साथ लेकर चलना, खण्ड स्तर पर संगठन/अभियान की रचना करना, कार्य के साथ कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए अच्छे वक्ताओं को तैयार करना, डीबीटैगरीडॉटकॉम वेबसाइट पर राष्ट्रद्रष्टा दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के भाषणों को सुनना एवं उनके द्वारा लिखित साहित्य को पढ़ना प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है।

उन्होंने आगामी 6 माह में ग्राम स्तर तक अभियान को पहुँचाना, दीपावली से पूर्व देशभर में स्वदेशी संकल्प यात्राएँ निकालने एवं प्रत्येक जिले में स्वदेशी मेले का आयोजन करने का आह्वान किया।

श्री आर. सुन्दरम ने कहा कि वर्तमान का समय स्वदेशी के लिए नया संदेश लेकर आ रहा है, जिसमें हम सब को स्वदेशी पर काम करने के लिए समाज एवं सरकार का सहयोग मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने सभी संबोधनों में स्वदेशी उत्पादों की खरीद की अपील कर रहे हैं। दूसरी ओर सामाजिक संगठनों में कनेरी मठ जैसे कई संगठन आगे आकर सहभागिता निभा रहे हैं। देश में कोरोना के बाद युवाओं एवं उद्यमियों ने स्वरोजगार, सामाजिक सेवा के साथ ही देश के विकास में भागीदार बनने में सफलता पाई है। वर्तमान में भारत में कनेक्टिविटी का विकास हुआ है, जिससे रेलमार्ग, हवाईमार्ग एवं सड़क मार्ग के कारण देश में कार्य करना आसान हुआ है। स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम एवं श्रीधर वेम्बू के अनुसार देश की युवाशक्ति, आर्थिक स्थिति, तकनीकी विकास की स्थिति एवं विकेन्द्रीकरण की नीतियां ही देश को आगे ले जाने में सक्षम हैं।

बैठक का समापन श्रीमती दीप्ति पयासी द्वारा राष्ट्रगीत वन्देमातरम् से हुआ। □□

स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में “व्यापारी जुटान”



स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में देश में पहली बार हुए ऐतिहासिक “व्यापारी जुटान” का आयोजन 15 एवं 16 सितम्बर 2025 को नागपुर में किया गया। श्री दीपक शर्मा ने इसके संयोजक एवं श्री अजय पत्की ने इसके समन्वयक के रूप में सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया। इस आयोजन को बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला, जिससे भविष्य में ऐसे ही आयोजन प्रांतों तथा जिलों में भी आयोजित करने का सामुहिक निर्णय किया गया, साथ ही देश के खुदरा व्यापार को नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड से बचाने के लिए एक मज़बूत ई कॉमर्स पालिसी एवं ऑन लाइन के लिए नियामक तंत्र की माँग भी सरकार से करी गई। देश के खुदरा व्यापारियों को भविष्य के टेक्नोलॉजी ड्रिवेन व्यापार के संबंध में जागरूक, शिक्षित एवं प्रशिक्षित करने का भी निर्णय लिया गया। हॉकर्स को गुणवत्ता और स्वच्छता मानदंडों पर प्रशिक्षित करने का अभियान भी शीघ्र चलाने का निर्णय लिया गया। “व्यापारी जुटान” का साझा घोषणा पत्र संलग्न है।

देश के प्रमुख व्यापारी संगठन – भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान (रजि.), हॉकर्स जॉइंट एक्शन कमिटी, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (रजि.) तथा अन्य 40 प्रमुख व्यापारी संगठनों के 250 से अधिक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

व्यापारी कल्याण बोर्ड, भारत सरकार, के अध्यक्ष श्री. सुनील सिंघी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर चाँदनी चौक से लोकसभा सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल, स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री आर. सुंदरम, अ.भा.संगठक श्री कश्मीरी लाल, सह संगठक श्री सतीश कुमार एवं श्री दीपक शर्मा ने प्रतिनिधियों को संबोधित किया। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बाबू लाल गुप्ता ने “व्यापारी जुटान” के साझा घोषणा पत्र को सहमति प्रदान की, वरिष्ठ महामंत्री श्री मुकुंद बिहारी मिश्रा ने अपनी सहभागिता और सहमति जताई।

समारोप सत्र में उपस्थित संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों की सर्व सहमति से बने इस घोषणा पत्र का वाचन कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री (सीए) बी.सी. भरतिया ने किया। इस अवसर पर कैट के सेक्रेटरी जनरल एवं चाँदनी चौक से लोकसभा सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (रजि.) के अध्यक्ष श्री रविकांत गर्ग, श्री संदीप बंसल अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (रजि.) भी मंच पर उपस्थित रहे।

भविष्य में इसके लिए एक सुगठित ढाँचा, कार्यालय, कोष, डिजिटल प्रचार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, फुल टाइम्स आदि पर भी सहमति बनी।

दिनांक 30.8.2025 को कार्यक्रम की पहली योजना बैठक में कैट ने इस कार्यक्रम को होस्ट करने का निवेदन किया जिसे सभी व्यापार संगठनों ने स्वीकार कर लिया। दिनांक 5.9.2025 को नई दिल्ली में आयोजित पहली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री दीपक शर्मा, श्री बाबू लाल गुप्ता, सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल, श्री मुकुंद बिहारी मिश्रा, श्री धर्मेन्द्र कुमार (अध्यक्ष, जॉइंट हॉकर्स एक्शन कमेटी), तथा श्री अशोक गोयल (अध्यक्ष, व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान) उपस्थित रहे। इस यशस्वी आयोजन में सभी संस्था/संगठन का विशेष सक्रिय सहयोग रहा। भविष्य में भी प्रांतों व जिलों में ऐसे जनजागरण आयोजन किए जाने की घोषणा हुई।

स्वजाम की राष्ट्रीय कार्यसमिति में विभिन्न विषयों पर चर्चा

उस्मानिया विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस के ऑडिटोरियम में 20 सितंबर 2025 (शनिवार) को स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक हुई। विभिन्न राज्यों से आये 95 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित बैठक में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक सीएआर सुन्दरम, राष्ट्रीय संगठन मंत्री कश्मीरलाल, राष्ट्रीय सह-संगठक श्री सतीश कुमार ने अपने विचार रखे। अवसर पर भारतीय आर्थिक स्वावलम्बन, स्वदेशी आधारित विकास, सामाजिक एवं अध्यात्मिक समन्वय, युवाओं में स्वदेशी चेतना का प्रसार सहित अन्य विषयों पर बैठक में चर्चा की गई। वक्ताओं ने अपने सम्बोधन के जरिये देश की अर्थव्यवस्था में स्वदेशी उत्पादों का महत्व समझाया। साथ सही आत्मनिर्भरता और स्थानीय आर्थिक शक्ति को सुदृढ़ बनाने हेतु ठोस कार्यानिति तैयार करने की दिशा में नई सोच का मार्ग प्रशस्त किया। राष्ट्रीय कार्यसमिति की यह बैठक भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वदेशी की भावना को और अधिक व्यापक बनाने पर केन्द्रित है। अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच, दक्षिण क्षेत्र के संयोजक

डॉ. एस. लिंगमूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक 'स्वदेशी-आत्म शक्ति' का विमोचन राष्ट्रीय संयोजक श्री आर. सुन्दरम, राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल एवं सह-संगठक श्री सतीश कुमार द्वारा किया गया।

स्वदेशी अपनाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा स्थानीय उत्पादों यथा हस्तशिल्प एवं खादी उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए जिला मुख्यालय फलोदी के दुर्ग में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। फलोदी विधायक मास्टर पब्बाराम विश्णोई व जिला कलक्टर श्वेता चौहान ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। साथ ही स्थानीय उत्पादों की लगी स्टालों का अवलोकन करते हुए आमजन से प्रदर्शनी में पधारकर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की, जिससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिले। दुर्ग में स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों, खादी उत्पादों, मिट्टी से बने उत्पादों, चित्रकारी सहित कुल 16 स्टॉल लगाई गई। इस दौरान विधायक पब्बाराम विश्णोई ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों व सामग्री का उपयोग करके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में योगदान दें। उन्होंने कहा कि जब आमजन स्वदेशी उत्पाद खरीदेंगे तो न केवल स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। उद्योग विभाग की महाप्रबंधक डॉ अंजुला आसदेव ने कहा कि प्रदर्शनी का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के कारीगरों एवं उद्यमियों को उचित मंच प्रदान करना है, जिससे वे अपनी कृतियों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकें। उन्होंने आमजन से अधिक से अधिक संख्या में प्रदर्शनी में पहुंचकर अवलोकन करने की अपील की। इस दौरान उपखंड अधिकारी पूजा चौधरी, नगर परिषद आयुक्त विक्रम सिंह चारण सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि व समाजसेवी उपस्थित थे।

दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर कार्यक्रम

विकासखंड हटा में राघवेंद्र सिंह हजारी महाविद्यालय में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वाधान में पंडित दीनदयाल जी की जन्म जयंती समारोह का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में प्रताप पटेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं आरती के उपरांत अपने उद्बोधन में बताया गया कि स्वदेशी हमारे भारत की सभ्यता

की नींव है। अगर हम स्वदेशी का उपयोग करते हैं तो हम अपने भारत की नींव को एवं अपने राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। ऑनलाइन खरीदारी ना करके हम अगर अपने क्षेत्र के अपने लोकल क्षेत्र के खरीद दुकानदारों से खरीदारी करते हैं तो हमारे भारत की एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हमारा मेहनत और ईमानदारी का पैसा बाहर की कंपनियों को ना जाकर, बाहर के उद्योगपतियों को इसका लाभ न होकर हमारे क्षेत्र के दुकानदारों एवं लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग समस्त व्यापारियों का इसका फायदा होगा और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वदेशी से हमारे भारत का विकास संभव है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने भारत राष्ट्र की उन्नति एवं भारतीय स्वदेशी तथा भारत की आर्थिक नींव को मजबूत करने तथा भारत के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का अथक प्रयास किया।

विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद कन्हैया लाल पटेल में भी अपने उद्बोधन में कहा कि हम ऑनलाइन चीज को ना खरीद कर अपने क्षेत्र की दुकानदारों में व्यापारियों से कोई भी सामान खरीदे और अपने समाज को एवं अपने राष्ट्र को एक उन्नतशील तथा विकसित भारत के रूप में एक आर्थिक शक्ति बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। तहसीलदार शिवराम चढ़ार ने भी अपने उद्बोधन में स्वदेशी से संबंधित है व्याख्यान दिया जिसमें हमें अपने भारत एवं अपने नजदीकी क्षेत्र से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करने तथा छोटी दुकानदारों से खरीदारी करने एवं ऑनलाइन खरीदारी न करने की बात कही। कार्यक्रम में विशिष्ट तिथि के रूप में भोला सराफ, सौरभ नेमा, अवधेश उपाध्याय, तहसीलदार हटा शिवराम चढ़ार, अतुल पन्या, गजेंद्र महाजन, गर्वेश राजपूत, पुष्पा सिंह, सुरेश नामदेव, सोमनाथ विश्वकर्मा तथा प्रिंसदीप खटीक, शिवानी लखेरा, नरेंद्र प्रताप सिंह तथा सीएमसीएलडीपी के छात्र-छात्राओं सहित कॉलेज के छात्र-छात्राओं की उपस्थिति कार्यक्रम में रही।

स्वदेशी के इस्तेमाल से भारत मजबूत होगा भारत: प्रो. सचदेवा

स्वदेशी जागरण मंच जिला कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित पांच दिवसीय स्वदेशी संकल्प यात्रा का शुभारंभ भद्रकाली मंदिर से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो सोमनाथ सचदेवा ने तिरंगा झंडा फहराकर किया। इस अवसर पर शहर की सामाजिक, धार्मिक, व्यापार मंडल आदि संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी स्वदेशी संकल्प यात्रा को शुभकामनाएं दी। कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने बताया कि ट्रम्प

ने टेरिफ लगाकर भारत देश के सामने चुनौती पेश की है, परंतु इस घड़ी में हमें सुझबुझ से काम लेना है। पहले जब भारत पोखरण परीक्षण कर न्यूक्लियर पावर बना था तब भी विदेशी शक्तियों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे लेकिन भारत के अडिग रहैए के कारण कुछ ही समय बाद उन्होंने वो प्रतिबंध हटा लिए थे। आज के टेरिफ टेररिज्म से निपटने के लिए स्वदेशी ही सबसे बड़ा हथियार है। हम अपने जीवन में सुबह से शाम तक स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे तो भारत देश आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत होगा। स्वदेशी हमारी मजबूत आर्थिक शक्ति का मूल आधार है। कुलपति ने बताया कि भारत ने कोविड में दौरान स्वदेशी वेक्सीन बनाकर दुनिया के सामने आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया।

युवा स्वयं बनें रोजगार सृजनकर्ता: जगदीश

आमदी के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा स्वदेशी उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जगदीश पटेल, प्रांत संयोजक स्वदेशी जागरण मंच छत्तीसगढ़ तथा विशिष्ट वक्ता के रूप में सुमन मुथा अधिवक्ता, आमदी नगर पंचायत अध्यक्ष ज्योति साहू, नामदेव राय, भारती राय एवं रामअवतार उपस्थित थे।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत एवं प्रभारी प्राचार्य डॉ. गौकरण प्रसाद जायसवाल के उद्बोधन से हुआ। उन्होंने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि स्वदेशी उद्यमिता आज के समय की सशक्त आवश्यकता है। मुख्य वक्ता जगदीश पटेल ने कहा कि भारत के स्वदेशी अभियान और स्वावलंबी भारत की संकल्पना को स्पष्ट किया उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के समय चलाए गए स्वदेशी आंदोलन केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं थे, बल्कि आत्मगौरव आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की ज्योति प्रज्वलित करने वाला अभियान था। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा के साथ कौशल को जोड़ें और केवल नौकरी की प्रतीक्षा न करें, बल्कि स्वयं रोजगार सृजनकर्ता बनें। श्री पटेल ने छत्तीसगढ़ के उन युवाओं के उदाहरण प्रस्तुत किए, जिन्होंने अपने नवाचार और परिश्रम से उद्यमिता का मार्ग अपनाकर समाज में नई पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी यदि स्वदेशी चेतना और उद्यमिता की राह पकड़ लें, तो आने वाला भारत और अधिक समृद्ध व सशक्त होगा। सुमन मुथा ने विद्यार्थियों को भारत में निर्मित वस्तुओं के उपयोग के लिए शपथ दिलाते हुए कहा कि यदि प्रत्येक नागरिक स्वदेशी

वस्तुओं को अपनाने का संकल्प लें, तो भारत विश्व में ! सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने मेक इन इंडिया एवं स्टार्ट-अप इंडिया जैसी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि आज भारत तेजी से वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ रहा है।

स्वदेशी ही एकमात्र विकल्प: अंकेश्वर



स्वदेशी जागरण मंच की स्वदेशी संकल्प यात्रा का जगह-जगह स्वागत किया गया। संयोजक डॉ. अजय जांगड़ा ने बताया कि जब यात्रा कुरुक्षेत्र के सेक्टर-3 पहुंची तो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि कैलाश सैनी ने स्वागत किया और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया।

उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारी सेनाएं बाहरी सुरक्षा कर रही हैं और ऑपरेशन सिंदूर से अपनी ताकत साबित की है, उसी तरह आंतरिक सुरक्षा के लिए भी आंतरिक ऑपरेशन सिंदूर जरूरी है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी अपनाना ही सच्चा राष्ट्र धर्म है। सरकार भी स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास कर रही है।

प्रांत संयोजक डॉ. अंकेश्वर प्रकाश ने कहा कि यह यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है और कुरुक्षेत्र जैसी ऐतिहासिक नगरी से स्वदेशी का संदेश मिलना विशेष महत्व रखता है। जैसे महाभारत में अन्याय के खिलाफ युद्ध लड़ा गया, वैसे ही आज विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी को अपनाना समय की मांग है। समाजसेवी सुदेश पाल व शिव कुमार ने अग्रसेन चौक पर फूलमालाओं से यात्रा का अभिनंदन किया।

उमरी में यात्रा प्रचार प्रमुख हरिकेश पपोसा ने बताया कि प्रतापगढ़ में राजेश सैनी की अध्यक्षता में सैकड़ों लोगों ने स्वागत किया। वहीं कोल्हापुर के सरपंच बलविंदर ने गांव में बड़े होर्डिंग लगवाने की घोषणा की। खेरी में स्कूल प्राचार्य सविता और मुनियारपुर में सरपंच लवदीप कोर ने यात्रा का स्वागत किया। सलेमपुर में मंडल अध्यक्ष विनोद, मेहमा राजेंद्र और तेजपाल ने ग्रामीणों संग पुष्पवर्षा की। बरोट गांव में गुरदीप बेदी, राजकुमार बेदी और सोनी राणा ने भी ग्रामीणों के साथ स्वागत किया। बोड़ला गांव में भी उत्साह देखने को मिला। □□

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी उद्यमिता विकास यात्रा

सचित्र झलक



दिल्ली



मध्य प्रदेश



बीकानेर



राउरकेला, उड़ीसा



भुवनाबाद



मेरठ



मैनपुरी



राजकोट, गुजरात



लखनऊ



शामली



हल्द्वानी, उत्तराखंड



हापड़

व्यापारी जुलन

15-16 सितंबर 2025 (नागपूर)



स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी उद्यमिता विकास यात्रा

सचित्र झलक



अवध



बदायूँ



मुजफ्फरनगर



उड़ीसा (प.)



उड़ीसा (प.)



शाहजहापुर (बुज)



सिक्किम



तमिलनाडु



विक्रमदेव विषयविद्यालय, उड़ीसा



उत्तर असम



उत्तराखंड



कांछला, प.उ.प्र.



गुवाहाटी, असम



गोंडा, अवध



कानपुर



जोधपुर



झांसी



त्रिपुरा

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर-8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022 से प्रकाशित, संपादक: अजेय भारती